



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934

No. 114]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISAKHA 10, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

फा. सं. 3-24/2012-बी एंड सीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)
की अधिसूचना संख्या 39 जो,—

(ए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० एस.ओ. 44 (ई) तथा 45(ई) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्जेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम,
2012 (2012 का 9)

भाग I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एंड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 कहा जाएगा।
 (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं: इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (ए) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) आशय है;
 (बी) "एंड्रसेबल सिस्टम" से आशय है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इसके संबद्ध सॉफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिन्हें एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से टेलीविजन सिग्नल एनक्रिप्टिड रूप में भेजे जा सकते हैं और जिन्हें केबल ऑपरेटर द्वारा सब्सक्राइबर को ऐसे सब्सक्राइबर की स्पष्ट रुचि और अनुरोध पर दिए गए प्राधिकार की सीमाओं के भीतर सब्सक्राइबर के परिसर में कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के जरिए एक एक्टिवेटिड कंडीशनल एक्सेस प्रणाली वाले उपकरण या उपकरणों द्वारा डि-कोड किया जा सकता है;
 (सी) "एजेंट या मध्यस्थ" से आशय है, कोई व्यक्ति जिसमें कोई समष्टि, व्यक्तियों का समूह, सार्वजनिक या कॉरपोरेट निकाय, फर्म या कोई संगठन या निकाय, जिसे किसी ब्रॉडकास्टर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा टीवी चैनलों के वितरक को टीवी चैनल उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
 (डी) "अ-ला-कार्ट" से आशय है, एक टीवी चैनल की पेशकश करने के संदर्भ में एकल आधार पर वैयक्तिक रूप से चैनल देने की पेशकश करना,
 (ई) "अ-ला-कार्ट दर" से आशय है, वह दर जिस पर टीवी चैनलों के वितरक या सब्सक्राइबर, जैसा भी मामला हो, को कोई एक चैनल देने की पेशकश की जाती है;
 (एफ) "प्राधिकरण" से आशय है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण;

(जी) "प्रसारक" से आशय है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, निगमित निकाय, कोई संगठन अथवा निकाय शामिल है जो कार्यक्रम सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा इसमें उसकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं;

(एच) "प्रसारण सेवाएं" से आशय है स्पेस से अथवा केबल के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिगनलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने की आशा की जाती है और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ माना जाएगा;

(आई) "बुके" अथवा "चैनलों के बुके" से आशय है चैनलों का संकलन जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हो।

(जे) "बुके दर" अथवा "बुके की दर" से आशय है वह दर जिस पर टीवी चैनलों के वितरक अथवा सब्सक्राइबर, जैसा भी मामला हो, को चैनलों के बुके की पेशकश की जाती है;

(के) "केबल ऑपरेटर" से आशय है ऐसा व्यक्ति जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा मुहैया कराता है अथवा जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधन और प्रचालन को नियंत्रित करता है या उसके लिए उत्तरदायी है; और जो निर्धारित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करता है।

(एल) "केबल सेवा" से आशय है कार्यक्रमों का केबल द्वारा ट्रांसमिशन जिसमें किसी प्रसारण टेलीविजन सिगनलों का केबलों द्वारा रि-ट्रांसमिशन भी शामिल है;

(एम) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" से आशय है क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और एसोसिएट सिगनल जनरेशन का सेट, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबर्स द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;

(एन) "कैरिज शुल्क" से आशय है अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों की प्लेसमेंट का ब्यौरा दिए बिना टीवी चैनल के ऐसे वितरक के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा संचालित प्लेटफार्म पर, उक्त प्रसारक के चैनल अथवा चैनलों के बुके (समूहों) के कैरिज के लिए किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के वितरक को भुगतान किया गया कोई शुल्क;

(ओ) "वाणिज्यिक सब्सक्राइबर" से आशय है कोई ऐसा सब्सक्राइबर जो सेवा प्रदाता को उसके द्वारा बताए गए स्थान पर कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है तथा ऐसे सिगनलों का अपने ग्राहकों, सदस्यों तथा ऐसी

किसी श्रेणी या व्यक्तियों के समूह, जिनकी अभिगम्यता ऐसे स्थान तक हो, के लाभ के लिए इस्तेमाल करता है;

(पी) "डीएस क्षेत्र" से आशय है ऐसे क्षेत्र जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के संदर्भ में प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए एक डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से एनक्रिप्टिड रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों को ट्रांसमिट या रि-ट्रांसमिट करना अनिवार्य है;

व्याख्या : इस उपखंड में "केबल ऑपरेटर" की अभिव्यक्ति में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर शामिल होगा।

(क्यू) "टीवी चैनलों के वितरक" से आशय है कोई व्यक्ति जिसमें कोई समष्टि, व्यक्तियों का समूह, पब्लिक या कॉर्पोरेट निकाय, फर्म या कोई ऐसा संगठन या निकाय शामिल है जो केबल के माध्यम से या स्पेस के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों द्वारा टीवी चैनलों को रि-ट्रांसमिट करता है जिन्हें आम जनता द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः रूप से प्राप्त करने की आशा की जाती है तथा ऐसे व्यक्ति में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर शामिल है, परंतु यह उसी तक सीमित नहीं है,

(आर) केबल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में "फ्री-टु-एयर चैनल" से आशय से है कोई ऐसा चैनल जिसके केबल पर रि-ट्रांसमिशन के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा ब्रॉडकास्टर को कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है।

(एस) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर" से आशय ऐसा केबल ऑपरेटर है जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11सी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया हो और जो या तो मल्टीपल सब्सक्राइबर्स द्वारा सीधे या एक या एक से अधिक केबल ऑपरेटरों के माध्यम से एक साथ प्राप्त करने के लिए प्रसारक से अथवा उसकी प्राधिकृत एजेंसियों से कार्यक्रम सेवा को प्राप्त करता है तथा उसे रि-ट्रांसमिट करता है तथा जो अपने कार्यक्रम सेवा को ट्रांसमिट करता है। इसमें उसके प्राधिकृत वितरण एजेंसियां भी शामिल हैं चाहे उन्हें जिस नाम से भी जाना जाए;

(टी) "सामान्य सब्सक्राइबर" से आशय है किसी ऐसे सब्सक्राइबर से है जो किसी सेवा प्रदाता से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और उसका इस्तेमाल अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता है;

(यू) "पे चैनल" से आशय ऐसे चैनल से है जिसके लिए केबल ऑपरेटर द्वारा ब्रॉडकास्टर को सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किया जाना होता है और केबल पर अपने रि-ट्रांसमिशन के लिए ब्रॉडकास्टर से विधिवत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(वी) "प्लेसमेंट शुल्क" से आशय है टीवी चैनल के ऐसे वितरक द्वारा अपने स्वामित्व वाले अथवा प्रचालित किए जाने वाले वितरण प्लेटफार्म पर अन्य ब्रॉडकास्टरों के चैनलों की तुलना में ऐसे ब्रॉडकास्टर के चैनलों के प्लेसमेंट के लिए टीवी चैनल के वितरक को ब्रॉडकास्टर द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क।

(डब्ल्यू) "कार्यक्रम" से कोई टेलीविजन प्रसारण आशय है तथा इसमें शामिल है—

- (i) फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;
- (ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य-दृश्य लाइव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण, तथा 'कार्यक्रम सेवा' अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार निकाला जाएगा;

(एक्स) "आरआईओ" से आशय है किसी पार्टी द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव जिसमें वे शर्तें निर्धारित की जाती हैं जिसे पूरा करने पर अन्य पार्टियां उस पार्टी से अंतःसंयोजन प्राप्त करने की हकदार होती हैं;

(वाई) "सेवा प्रदाता" से आशय है सेवा प्रदाता के रूप में सरकार और इसमें शामिल हैं लाइसेंसधारी तथा कोई प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर अथवा टीवी चैनलों का वितरक;

(जेड) "सेट टॉप बॉक्स" से आशय है कोई ऐसा उपकरण जो किसी टेलीविजन पर जोड़ा जाता है या उसका एक भाग है और जिससे सब्सक्राइबर को किसी एड्रेसेबल प्रणाली के जरिए सब्सक्राइड चैनल अनक्रिप्टिड और डिस्क्रेम्बलड रूप में प्राप्त होते हैं;

(जैडए) "सब्सक्राइबर" आशय व्यक्ति से है जो सेवा प्रदाता को बताए गए किसी स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसमिट किए बगैर सेवा प्रदाता के सिग्नल प्राप्त करता है तथा इसमें साधारण सब्सक्राइबर और वाणिज्यिक सब्सक्राइबर, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से इससे हटाया न गया हो, शामिल हैं;

(जैडबी) "सब्सक्राइबर आधार" से आशय है डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में दर्शाई गई सब्सक्राइबरों की संख्या;

(जैडसी) "सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली" से आशय है कोई प्रणाली या उपकरण जो सब्सक्राइबर का नाम और पता, सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब्ड चैनल या चैनलों के बुके, प्रणाली में यथापरिभाषित चैनलों के बुके या चैनलों का मूल्य, किसी चैनल या चैनलों के बुके की एक्टिवेशन या डिएक्टिवेशन की तारीख और समय, सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड पर किए गए सभी कार्यों का एक लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर को दिए गए इनवॉइस और भुगतान की गई धनराशि या प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड तथा ब्योरा एकत्रित करता है;

(जैडडी) "टीवी चैनल" से आशय है ऐसा चैनल जिसे निम्न के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है—

(क) 2 दिसंबर, 2005 को सं.1501/2/2002-टीवी(1) (पार्ट.) के तहत जारी भारत से अपलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश; अथवा

(ख) 11 नवम्बर, 2005 को सं.13/2/2002-बीपीएंडएल/बीसी-IV के तहत जारी टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए नीति-निर्देश;

समय-समय पर यथासंशोधित अथवा भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) द्वारा अपलिंकिंग अथवा डाउनलिंकिंग के लिए समय-समय पर जारी ऐसे दिशानिर्देश तथा 'चैनल' शब्द का संदर्भ 'टीवी चैनल' के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(जैडई) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या अन्य विनियमों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है;

भाग II

अंतःसंयोजन

3. अंतःसंयोजन से संबंधित सामान्य उपबंध: (1) टीवी चैनलों का कोई भी प्रसारक किसी ऐसी प्रैक्टिस या क्रियाकलाप में नहीं लगेगा या कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा जिसमें उनके चैनल के वितरण के लिए कोई मल्टी प्रणाली ऑपरेटर के साथ कोई ऐसी अन्य संविदा करना शामिल है जो किसी अन्य मल्टी प्रणाली ऑपरेटर को वितरण हेतु ऐसे टीवी चैनल प्राप्त करने से रोक सकते हैं।

(2) प्रत्येक प्रसारक, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जो कि निर्धारित चैनल क्षमता रखता है। को अनुरोध करने पर बिना भेदभाव के अपने टीवी चैनल उपलब्ध कराएगा।

परंतु यह कि इस उस विनियम में निहित कोई भी तथ्य उस मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पर लागू नहीं होगा जिसने भुगतान में चूक की है।

परंतु यह भी कि कोई ऐसी शर्त थोपना जो अतर्कसंगत हो, अनुरोध की मनाही मानी जाएगी।

(3) प्रत्येक प्रसारक या उनके प्राधिकृत एजेंट, अपने इंटरकनेक्शन प्रस्ताव के संदर्भ अथवा परस्पर सहमति के अनुसार, अनुरोध प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराएगा और यदि टीवी चैनलों के लिए सिगनल उपलब्ध कराने के अनुरोध पर सहमति नहीं बनती है तो, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सिगनल उपलब्ध कराने से मना करने संबंधी ऐसे कारणों को अनुरोध किए जाने के 60 दिन के भीतर सूचित किया जाएगा।

(4) प्रसारक के साथ अंतःसंयोजन प्राप्त करते समय प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए संस्थापित अपनी डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली, इन विनियमों की अनुसूची-I में डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली के आवश्यकता के अनुरूप है।

परंतु यदि प्रसारक पाता है कि टीवी चैनल के वितरण के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रयोग की जा रही डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली, अनुसूची-I में विनिर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं है तो वह उस मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को सूचित करेगा जो मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड या समय-समय पर दिए गए निर्देश के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्धारित किसी अन्य एजेंसी से अपनी डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा कराएगा और उस एजेंसी से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि उसकी प्रणाली, इन विनियमों की अनुसूची-I में आवश्यकता के अनुरूप है।

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में उल्लिखित एजेंसी के निष्कर्ष अंतिम होंगे।

(5) एक प्रसारक से किसी विशिष्ट टीवी चैनल के सिगनल की मांग करने वाला मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, उस चैनल को अपने वितरण प्लेटफार्म पर प्रसारित करने के लिए कैरिज शुल्क की मांग नहीं करेगा।

(6) किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को सिगनल उपलब्ध कराने से पहले यदि कोई प्रसारक सिगनल उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्व-शर्त के रूप में किसी विशेष स्लॉट में अपने चैनल के प्लेसमेंट पर जोर देता है तो ऐसी पूर्व-शर्त को अतर्कसंगत शर्त थोपना माना जाएगा।

(7) कोई ब्राडकास्टर या उसका प्राधिकृत एजेंट जो ब्रॉडकास्टर की ओर से भुगतान प्राप्त करता है, वह मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को सिगनल प्रदान करने के लिए मासिक इनवॉइस जारी करेगा। ऐसे इनवॉइस में भुगतान की निर्धारित तारीख के साथ वर्तमान देय राशि या बकाया, यदि कोई है, स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा।

(8) केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4ए की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रचालनरत प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए अनिवार्य किया गया है कि वह डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से एनक्रिप्टेड रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों को ट्रांसमिट अथवा रि-ट्रांसमिट करे और उसके पास मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के परिचालन वाले क्षेत्र के लिए उक्त अधिसूचना में उल्लिखित तारीख तक कम से कम 500 चैनल चलाने की क्षमता होनी चाहिए।

परंतु कि मुंबई नगरपालिका के सीमा क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कोलकाता महानगर तथा चेन्नई महानगर क्षेत्र में प्रचालनरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, 30 जून, 2012 को न्यूनतम 200 चैनल चलाने की क्षमता प्राप्त करेगा और यह क्षमता 1 जनवरी, 2013 तक बढ़ा कर कम से कम 500 चैनल की जाएगी।

परंतु यह भी कि उप-विनियम (12) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रचालनरत कम से कम 25 हजार के सब्सक्राइबर आधार वाले सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर 01 अप्रैल, 2013 तक न्यूनतम 500 चैनल चलाने की क्षमता प्राप्त करेंगे।

(9) कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, किसी प्रसारक से कोई ऐसा समझौता अथवा व्यवस्था नहीं करेगा जिससे किसी अन्य प्रसारक को ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के केबल नेटवर्क से एक्सेस प्राप्त करने पर रोक लगे।

(10) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के अंदर अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार या जैसे परस्पर सहमति की गई हो, किसी प्रसारक या उसके प्राधिकृत एजेंट या मध्यस्थ को बिना किसी भेदभाव के अपने नेटवर्क पर एक्सेस प्रदान कराएगा और यदि एक्सेस नहीं करा सकने में सक्षम होगा तो, अनुरोध करने वाले को कारण सहित, अनुरोध की तारीख से 60 दिन के अंदर संसूचित किए जाएंगे।

परंतु यदि कोई ब्रॉडकास्टर अपने ऐसे क्षेत्रीय भाषा, के चैनल, जो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा न हो जहां मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रचालनरत हो, अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के अलावा चैनल की पेशकश करता है और वह मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में प्रकाशित समान कैरिज शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार न हो तो, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह ब्रॉडकास्टर के चैनल को चलाए।

परंतु यह भी कि इस उप-विनियम में दी गई कोई भी बात उस प्रसारक पर लागू नहीं होगी जो कैरिज शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान में चूक जारी हों;

परंतु यह भी कि केवल टीवी नेटवर्क पर एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए अतर्कसंगत शर्त लगाना, एक्सेस के लिए अनुरोध से मना करना माना जाएगा।

परंतु यदि किसी चैनल का पिछले 6 महीनों का औसत सब्सक्रिप्शन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर आधार के 5 प्रतिशत से कम अथवा 5 प्रतिशत के बराबर हो, जिसे पिछले 6 महीने सब्सक्रिप्शन के औसत

के रूप में लिया गया है, तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए चैनल के डिसकनेक्शन की तारीख से अगले एक वर्ष के लिए इन प्रावधानों के अंतर्गत चैनल चलाना अनिवार्य नहीं होगा।

(11) यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रसारक को अपने नेटवर्क पर एक्सेस प्रदान करने से पहले, ऐसे प्रसारक के चैनल को एक विशिष्ट स्लॉट या बुके (समूह) में रखने पर जोर देता है तो, ऐसी पूर्व शर्त को अनुचित शर्त थोपना माना जाएगा।

(12) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपना संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित करेगा, जिसमें वह प्रसारक के चैनल को कैरी करने लिए कैरिज शुल्क का प्रकाशन करेगा जिसके लिए प्रसारक ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से अनुरोध नहीं किया हो।

परंतु यह कि किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर सभी ब्रॉडकास्टरों से एक समान कैरिज शुल्क की मांग करेगा तथा अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव कैरिज शुल्क को प्रकाशित करेगा जो इस प्रकार के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष तक वृद्धि नहीं करेगा।

(13) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या उसके प्राधिकृत एजेंट, जो ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की ओर से ब्रॉडकास्टर से कैरिज शुल्क का भुगतान प्राप्त करता है, वह ऐसे ब्रॉडकास्टर को मासिक इनवॉइस जारी करेगा और उस इनवॉइस में स्पष्ट रूप से वर्तमान देय राशि तथा बकाया राशि विनिर्दिष्ट करेगा। इसके साथ-साथ भुगतान की निर्धारित तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(14) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या उनके प्राधिकृत एजेंट, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के अंदर अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार या जैसे परस्पर सहमति की गई हों, किसी केबल ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराएगा और यदि टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है तो सिगनल उपलब्ध कराने से मना करने के कारण, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को अनुरोध की तारीख से 60 दिन के अंदर संसूचित किए जाएंगे।

(15) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या उसके प्राधिकृत एजेंट, जो ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की ओर से स्थानीय केबल ऑपरेटर से सिगनल देने के लिए भुगतान प्राप्त करता है, वह ऐसे स्थानीय केबल

ऑपरेटर को मासिक इनवॉइस जारी करेगा और उस इनवॉइस में स्पष्ट रूप से वर्तमान देय राशि तथा बकाया राशि विनिर्दिष्ट करेगा। इसके साथ-साथ भुगतान की निर्धारित तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(16) इन विनियमों के अंतर्गत बकाया राशि के लिए की जाने वाले प्रत्येक मांग के साथ उस अवधि, जिससे बकाया धनराशि संबंधित है, के लिए इनवॉइस की सेवा का प्रमाण भी लगाया जाएगा।

अध्याय—III

संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव

4. **संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव से संबंधित सामान्य प्रावधान** — (1) प्रत्येक प्रसारक, इन विनियमों के प्रारंभ के 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसमें इस विनियम की अनुसूची-II में यथा उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें निर्दिष्ट की गई हों और इसे उसके वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

परंतु कोई प्रसारक, डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के विभिन्न प्रकारों के लिए भिन्न-भिन्न अंतःसंयोजन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) कोई प्रसारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी सब्सक्राइबर को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने से किसी डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली ऑपरेटर को नहीं रोकेगा।

(3) कोई प्रसारक, वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों की विभिन्न श्रेणियों को मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा सिगनलों की आपूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव विनिर्दिष्ट कर सकता है जैसे:

(ए) तीन सितारा और उससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल;

(बी) हैरिटेज होटल जैसेकि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए होटलों के वर्गीकरण के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(सी) पचास या इससे अधिक कमरों वाला, बोर्डिंग और लॉजिंग उपलब्ध कराने वाला कोई अन्य होटल, मोटल, इन्न और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान; और

विशेष अवसरों पर और कार्यक्रम देखने के लिए लागू होने वाले कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्थान पर पचास या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा देखे जाने वाले कार्यक्रम टेलीकॉस्ट करने के लिए विभिन्न संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव भी विनिर्दिष्ट कर सकता है;

परंतु सामान्य सब्सक्राइबर के लिए लागू होने वाले संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट किए गए वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के अलावा अन्य वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए भी लागू होंगे।

(4) प्रत्येक प्रसारक इन विनियमों के प्रारंभ होने के 30 दिन के अंदर अपने मौजूदा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में संशोधन करेगा ताकि उन्हें इन विनियमों के उपबंधों के अनुकूल बनाया जा सके।

(5) कोई प्रसारक जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात अपना प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालन के प्रारंभ से 30 दिन पहले प्राधिकरण को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और अपनी वेबसाइट पर इस प्रस्ताव को प्रकाशित करेगा।

(6) प्रत्येक प्रसारक सात दिन के अंदर प्राधिकरण को, अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ इन संशोधनों को उसी प्रकार जैसे मूल संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था, अपनी वेबसाइट पर भी संशोधनों को प्रकाशित करेगा।

(7) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, इन विनियमों के प्रारंभ के 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रसारक को अपने नेटवर्क में एक्सेस देने के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें निर्दिष्ट की गई हों और इसे उसकी वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(8) कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात अपना प्रचालन आरंभ करता है, अपने प्रचालन के प्रारंभ से पहले प्राधिकरण को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रसारक को अपने नेटवर्क में एक्सेस देने के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें निर्दिष्ट की गई हों और इसे उसकी वेबसाइट में प्रकाशित करेगा।

अध्याय— IV

अंतःसंयोजन करार

5. अंतःसंयोजन करार से संबंधित सामान्य प्रावधान — (1) कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर गैर-पक्षपातपूर्ण शर्तों पर प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की शर्तों के साथ प्रसारक के साथ करार कर सकता है।
- (2) ऐसा प्रसारक जो इन विनियमों के प्रारंभन के पश्चात संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित करता है, सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को यह विकल्प देगा कि वे संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार करार करें और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को यह छूट होगी कि वह नया करार करे या मौजूदा करार को जारी रखे।
- (3) प्रत्येक प्रसारक, इन विनियमों के तहत प्रकाशित अंतःसंयोजन प्रस्ताव की निबंधन व शर्तों के अंतर्गत परस्पर सहमति के आधार पर किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंदर अंतःसंयोजन करार या विद्यमान अंतःसंयोजन करार को संशोधित करेगा।
- (4) प्रत्येक प्रसारक अ-ला-कार्टे आधार पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को अपने सभी चैनलों की पेशकश करेगा:
- बशर्ते कि प्रसारक अ-ला-कार्टे आधार पर अपने सभी चैनलों की पेशकश के अलावा बुके के रूप में अपने चैनलों की पेशकश कर सकता है।
- (5) कोई प्रसारक किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगा कि वह अपने चैनल या चैनलों का बुके को किसी पैकेज, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रस्तावित किए गए किसी पैकेज या योजना में शामिल करें।
- (6) पे चैनलों के प्रसारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने समस्त इन्टर कनेक्शन अनुबंधों की निबंधन और शर्तों को लिखित रूप में रखें/करें।

- (7) लिखित इन्टर कनेक्शन अनुबंध किए बिना, पे चैनल का कोई भी प्रसारक, किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा।
- (8) विनियम (7) अथवा (8) के कोई भी प्रावधान, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही पर, ऐसे न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय सहित, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय के अनुसरण में अथवा अनुपालन में, किसी प्रसारक द्वारा सिगनल उपलब्ध कराने अथवा टीवी चैनलों के सिगनलों की आपूर्ति बनाए रखने पर लागू नहीं होंगे।
- (9) किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ इन्टर कनेक्शन का अनुबंध करने वाले पे चैनलों के प्रत्येक प्रसारक का यह दायित्व होगा कि इन्टर कनेक्शन अनुबंध की हस्ताक्षरित प्रति ऐसे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को सौंपे तथा अनुबंध के निष्पादन की तिथि के 15 दिन के भीतर इस संबंध में पावती प्राप्त करें।
- (10) यदि प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ किए गए अपने इन्टर कनेक्शन अनुबंध को संशोधित करना चाहता है तो इसके द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को तीस दिन का नोटिस दिया जाएगा ऐसे और अनुबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन प्रसारक द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत प्रकाशित, इन्टर कनेक्शन प्रस्ताव की निबंधन एवं शर्तों के संदर्भ अथवा जैसा भी परस्पर सहमति बनी हो, के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यदि प्रसारक एवं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, इन्टर कनेक्शन अनुबंध करने में असफल रहते हैं तो, ऐसा प्रसारक अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, अधिनियम की धारा 14ए अथवा, उस समय के लिए प्रचलित किसी अन्य कानून के पूर्वाग्रह के बिना किसी भी समय, इस प्रकार का अनुबंध करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने को सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकते हैं तथा प्राधिकरण द्वारा प्रसारक और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को ऐसे निदेश, जैसे कि इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाए, जारी किए जाएंगे।

(12) उप-विनियम 3 में दी गई कोई भी बात किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित निर्णयाधीन किसी मामले या मुद्दे पर लागू नहीं होगी या ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी जिनके संबंध में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा डिक्री, अवार्ड या कोई आदेश पारित किया गया है।

(13) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और उससे जुड़े स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच इन्टर कनेक्शन अनुबंध में स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं तथा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटर को इन सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभासों के विवरण होंगे।

(14) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एवं उससे जुड़े स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच हुए इन्टर कनेक्शन करार में उपभोक्ताओं के बिल जनित करने के उत्तरदायित्व एवं समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी सेवा की गुणवत्ता के विनियमों की अनुरूपता के अनुसार मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एवं उससे जुड़े स्थानीय केबल ऑपरेटर की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को स्पष्टतः चिन्हित किया जाए।

(15) किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को इस बात की छूट होगी कि वह प्रसारक द्वारा उसे उपलब्ध कराए गए चैनलों के बुके से सब्सक्राइबर को प्रस्तावित चैनलों का पैकेजिंग तय करे:

परंतु यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर सब्सक्राइबर को प्रसारक द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों को पूरे बुके की पेशकश नहीं करता है परंतु उस बुके के चैनलों के पैकेज या बुके के केवल कुछ चैनलों की पेशकश इस तरीके से करता है जिसके परिणामस्वरूप उस बुके के भिन्न-भिन्न चैनलों का सब्सक्राइबर आधार भिन्न-भिन्न हो जाता है तो उस बुके के लिए प्रसारक को किए जाने वाले भुगतान का परिकलन बुके के उस चैनल के सब्सक्राइबर आधार पर किया जाएगा जिसका उच्चतर सब्सक्राइबर आधार हो।

(16) प्रत्येक सेवा प्रदाता, मौजूदा करार की समाप्ति से पहले एक नया करार करेगा और यदि उक्त करार की समाप्ति से पहले सेवा प्रदाता, नया करार करने में विफल रहता है तो मौजूदा करार के उपबंध, सेवा प्रदाताओं के बीच नया करार करने तक या मौजूदा करार की समाप्ति की तारीख से अगले तीन महीने, इनमें से जो भी पहले हो, तक लागू होते रहेंगे और यदि सेवा प्रदाता, उक्त तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले कोई करार करने में समर्थ हैं तो नया करार, पिछले करार की समाप्ति की तारीख से लागू होगा।

परंतु यदि सेवा प्रदाता कोई नया करार करने में समर्थ नहीं होते हैं तो वे दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित तीन सप्ताह का नोटिस देकर टीवी चैनलों के सिगनल डिसकनेक्ट करने के हकदार हो सकते हैं, उक्त नोटिसों में से एक नोटिस उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जिसके लिए करार लागू है।

- (17) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने समस्त इन्टर कनेक्शन अनुबंधों की निबंधन और शर्तों को लिखित रूप में रखें/करें।
- (18) लिखित इन्टर कनेक्शन अनुबंध किए बिना, कोई भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, किसी भी जुड़े हुए स्थानीय केबल ऑपरेटर को टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध नहीं कराएगा।
- (19) विनियम (17) अथवा (18) के कोई भी प्रावधान, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लम्बित किसी कार्यवाही पर, ऐसे न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय सहित, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय के अनुसरण में अथवा अनुपालन में, किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सिगनल उपलब्ध कराने अथवा टीवी चैनलों के सिगनलों की आपूर्ति बनाए रखने पर लागू नहीं होंगे।
- (20) किसी/किन्हीं जुड़े हुए स्थानीय केबल ऑपरेटर/ऑपरेटरों के साथ इन्टर कनेक्शन का अनुबंध करने वाले प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का यह दायित्व होगा कि इन्टर कनेक्शन अनुबंध की हस्ताक्षरित प्रति ऐसे केबल ऑपरेटर को सौंपे तथा अनुबंध के निष्पादन की तिथि के 15 दिन के भीतर इस संबंध में पावती प्राप्त करें।
- (21) कोई सेवा प्रदाता, किसी अन्य सेवा प्रदाता से उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क के रूप में एक न्यूनतम गारंटी धनराशि की मांग नहीं करेगा।

अध्याय—V

टीवी चैनलों के सिगनलों का डिसकनेक्शन

6. टीवी चैनल के सिगनलों का डिसकनेक्शन: (1) यदि कोई प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को तीन सप्ताह का नोटिस दिए बिना, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तावित डिसकनेक्शन के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के किसी टीवी चैनल का सिगनल डिसकनेक्ट नहीं करेगा।
- (2) कोई भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, किसी जुड़े हुए स्थानीय केबल ऑपरेटर के टीवी चैनलों के सिगनलों का डिसकनेक्शन, प्रस्तावित डिसकनेक्शन के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए ऐसे स्थानीय केबल ऑपरेटर को तीन सप्ताह का नोटिस दिए बिना नहीं करेगा।

- (3) कोई भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, किसी भी टीवी चैनल के रि-ट्रांसमिशन का डिस्कनेक्शन, प्रसारक को प्रस्तावित डिस्कनेक्शन के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए तीन सप्ताह का नोटिस दिए बिना नहीं करेगा ।
- (4) कोई भी स्थानीय केबल ऑपरेटर, किसी भी टीवी चैनल के रि-ट्रांसमिशन का डिस्कनेक्शन, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को प्रस्तावित डिस्कनेक्शन के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए तीन सप्ताह का नोटिस दिए बिना नहीं करेगा ।
- (5) उप विनियम (1),(2),(3) और (4) के अंतर्गत टीवी चैनलों के सिगनलों के डिस्कनेक्शन का प्रत्येक नोटिस, और उप विनियम (2), (3) और (4) के अंतर्गत टीवी चैनलों के रि-ट्रांसमिशन के डिस्कनेक्शन का प्रत्येक नोटिस, उस राज्य के अग्रणी समाचार पत्रों, जिनमें सेवा प्रदाता द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें से एक नोटिस स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।
- (6) उप विनियम (1),(2),(3) और (4) में विनिर्दिष्ट तीन सप्ताह की अवधि, नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से अथवा सेवा प्रदाता को नोटिस सुपुर्द करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रारंभ होगी, तथा यदि समाचार पत्रों में नोटिस अलग-अलग तिथियों पर प्रकाशित हुए हों तो तीन सप्ताह की अवधि की गणना दोनों तिथियों में से बाद वाली तिथि से की जाएगी ।

अध्याय—VI

विविध

7. फ्री-टु-एयर चैनल का पे चैनल में या पे चैनल का फ्री-टु-एयर चैनल में रूपांतरण — फ्री-टु-एयर या पे चैनल घोषित किया गया कोई चैनल, कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वही चैनल बना रहेगा और किसी फ्री-टु-एयर चैनल को पे चैनल अथवा पे चैनल को फ्री-टु-एयर चैनल में रूपांतरण करने से पहले कोई प्रसारक, प्राधिकरण को सूचित करेगा और रूपांतरण से पहले दो स्थानीय समाचार पत्रों में एक महीने का नोटिस देगा जिनमें से एक उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जिस क्षेत्र में यह रूपांतरण किया जा रहा होता है ।

8. प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप – प्राधिकरण उपभोक्ता या सेवा प्रदाता के हितों की रक्षा करने या प्रसारण तथा केबल सेक्टर की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने या विनियमों के अनुपालना को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हस्तक्षेप कर सकता है और सेवा प्रदाता को यह निर्देश दे सकता है कि वह इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपना संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव संशोधित करे।

9. रिपोर्टिंग की शर्तें – (1) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर इन विनियमों की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा पर प्राधिकरण को प्रसारक और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के साथ उसके द्वारा किए गए सभी अंतःसंयोजन करार और उसमें बाद में किए गए संशोधनों को सूचित करेगा।

(2) प्रत्येक मौजूदा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर 31 जुलाई, 2012 तक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए सभी अंतःसंयोजन करार और इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले उनमें किए गए संशोधन प्रस्तुत करेगा।

(3) इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात अपनी सेवाएं आरंभ करने वाला प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्राधिकरण को करार करने के 30 दिन के अंदर या 31 जुलाई 2012 तक, इनमें से जो भी बाद में हो, अपने अंतःसंयोजन करार प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(4) प्रसारक समय-समय पर संशोधित अंतःसंयोजन करार (प्रसारण और केबल सेवाएं) विनियम, 2004 (2004 का 15) के रजिस्टर के अंतर्गत उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ-साथ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को उसके द्वारा भुगतान किए गए कैरिज शुल्क का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। अब से यह इस सूचना में प्रसारक द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को भुगतान किए जाने वाले कैरिज शुल्क के ब्योरे भी शामिल होंगे।

वसी अहमद, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/142/12]

टिप्पणी – इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 के उद्देश्य और कारण स्पष्ट किए गए हैं।

अनुसूची-1

डिजिटल एंड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली की आवश्यकताएं

(ए) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) एवं सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस):

1. कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के वर्तमान वर्जन की कभी हैकिंग नहीं की गई होनी चाहिए।
2. किसी उपकरण अथवा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से फिंगर प्रिंटिंग समाप्त नहीं होनी चाहिए।
3. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैडएंड से एसटीबी तथा वीसी को जोड़ा जाना चाहिए।
4. दोनों प्रणालियों के जरिए साथ-साथ एसएमएस करने के लिए एक्टिवेशन तथा डिएक्टिवेशन के लिए एसएमएस तथा सीए को एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीए प्रणाली, सभी एक्टिवेशन के लॉग को जनरेट करने में भी समर्थ होनी चाहिए।
5. यह पता होना चाहिए कि सीए कंपनी के पास हैकिंग की परिचित घटना के मामले में सीए के प्रयोग को अपग्रेड करने की क्षमता है।
6. एसएमएस तथा कैस, चैनल दर, चैनल तथा एसटीबी दर, एसटीबी आधार पर अलग सब्सक्राइबरों को एंड्रेस करने में समर्थ होने चाहिए।
7. एसएमएस, कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए तथा यह सब्सक्राइबर के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचना तथा डाटा को रिकॉर्ड करने में समर्थ होना चाहिए।

ए. यूनीक कस्टमर आईडी

बी. सब्सक्रिप्शन कान्ट्रैक्ट नंबर

सी. सब्सक्राइबर का नाम

डी. बिल के लिए पता

ई. इन्टॉलेशन का पता

एफ. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर

जी. मोबाइल टेलीफोन नंबर

एच. ई-मेल आईडी

आई. सर्विस/पैकेज सब्सक्राइब किया गया

जे. यूनीक एसटीबी नंबर

के. यूनीक वीसी नंबर

8. एसएमएस निम्नलिखित के लिए समर्थ होना चाहिए -

ए. एक्टिवेशन, डिएक्टिवेशन आदि के अनुसार पुराने डाटा को देखना तथा प्रिंट लेना।

बी. प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स वीसी यूनिट का स्थान

सी. एसएमएस किसी भी वांछित समय पर रिपोर्ट प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए :-

- (i) प्राधिकृत सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या
- (ii) नेटवर्क पर सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या
- (iii) किसी खास समय पर किसी खास सेवा के सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या
- (iv) अ-ला-कार्ट आधार पर सब्सक्राइबर द्वारा चयनित किए गए चैनलों का ब्यौरा।
- (v) पैकेज में चैनलों का पैकेजवार ब्यौरा।
- (vi) पैकेजवार सब्सक्राइबर्स की संख्या।
- (vii) किसी खास चैनल अथवा पैकेज पर सब्सक्राइबर्स की आयु।
- (viii) पिछले 2 वर्षों की अवधि के लिए ऊपर उल्लिखित सभी डाटा का पूर्ण विवरण।

9. एसएमएस तथा कैस, को सिस्टम पर एक मिलियन सब्सक्राइबर्स को संभालने में समर्थ होना चाहिए।
10. सीए एवं एसएमएस प्रतिष्ठित संगठन के होने चाहिए और उनका ऐसे अन्य पे टेलीविजन सेवाओं द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा होना चाहिए, जिनके ग्लोबल पे टीवी बाजार में कुल मिलाकर कम से कम एक मिलियन सब्सक्राइबर हों।
11. कैस प्रणाली प्रदाता किसी खास चैनल अथवा किसी खास पैकेज पर एक्टिवेशन का मासिक लॉग मुहैया कराने में समर्थ होना चाहिए।
12. एसएमएस, कंटेंट लागत, उपकरणों का किराया, कर आदि जैसे मदवार बिल जनरेट करने में समर्थ होना चाहिए।
13. भारत में वर्ष भर 24 x 7 आधार पर प्रणाली को चलाने के लिए सीए तथा एसएमएस प्रणाली के सप्लायर्स के पास तकनीकी क्षमता होनी चाहिए।
14. कैस एवं एसएमएस में वीसी नंबर तथा एसटीबी नंबर, जो विगत में पायरेसी में शामिल हों, को टैग करने तथा ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि वीसी अथवा एसटीबी को पुनः न लगाया जाना सुनिश्चित हो सके।

(बी) फिंगरप्रिंटिंग

1. रिमोट के किसी बटन को दबाने से फिंगरप्रिंटिंग हटना नहीं चाहिए।
2. फिंगर प्रिंटिंग, वीडियो के सबसे ऊपर वाली परत में होनी चाहिए।

3. फिंगर प्रिंटिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि यह यूनीक एसटीबी नंबर अथवा यूनीक व्यूइंग कार्ड (वीसी) नंबर की पहचान कर सके।
4. फिंगर प्रिंटिंग, एसटीबी की सभी स्क्रीनों में दिखाई दी जानी चाहिए, जैसे कि मेन्यु, ईपीजी आदि।
5. फिंगर प्रिंटिंग की लोकेशन हैडएंड से बदलती रहनी चाहिए और यह व्यूइंग उपकरण में कहीं भी हो सकती है।
6. फिंगर प्रिंटिंग को करेक्टरों की संख्या देनी चाहिए ताकि यूनीक एसटीबी और/अथवा वीसी की पहचान हो सके।
7. फिंगर प्रिंटिंग, ग्लोबल तथा अलग-अलग एसटीबी के आधार पर संभव होनी चाहिए।
8. समय, स्थान, अवधि तथा फ्रीक्वेंसी के संबंध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना एमएसओ/एलसीओ द्वारा ओवर्ट फिंगर प्रिंटिंग तथा संबंधित प्रसारकों के ऑन स्क्रीन डिसप्ले (ओएसडी) मैसेज को प्रदर्शित करना चाहिए।
9. कोई कॉमन इंटरफेस कस्टमर प्रिमिसेस इक्यूपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
10. एसटीबी प्रावधान होना चाहिए कि ओएसडी को कभी भी डिसएबल नहीं किया जा सकेगा।

(सी) सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी)

1. सभी एसटीबी, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली से सज्जित होने चाहिए।
2. सभी एसटीबी हैडएंड द्वारा इनसर्ट कंडीशनल एक्सेस को डिफ्रिक्ट करने में समर्थ होने चाहिए।
3. एसटीबी, फिंगर प्रिंटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी, इनटाइटिलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) तथा इनटाइटिलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम) आधारित फिंगरप्रिंटिंग दोनों के लिए सहायक होना चाहिए।
4. एसटीबी, हैडएंड से अलग से एड्रेसेबल होनी चाहिए।
5. एसटीबी, हैडएंड से मैसेज प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।
6. ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग तक अलग-अलग एसटीबी मैसेजिंग का प्रावधान होना चाहिए।
7. ग्लोबल मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग तथा अलग-अलग एसटीबी मैसेजिंग का प्रावधान होना चाहिए।
8. एसटीबी में फोर्सड मैसेजिंग क्षमता होनी चाहिए।
9. एसटीबी, बीआईएस के अनुरूप ही होना चाहिए।
10. एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें एसटीबी के भीतर डिफ्रिक्टन एवं डिक्म्पैशन के बीच कंटेंट सुरक्षित हों।
11. ओवर द एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए एसटीबी, ओवर द एयर एड्रेसेबल होना चाहिए।

अनुसूची II

शर्तें एवं निबंधन जो अनिवार्यतः डिजिटल एंड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम प्लेटफार्म के लिए प्रसारणकर्ता और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के बीच अंतःसंबंध हेतु संदर्भित परस्पर संबंध के भाग होने चाहिए।

लाइसेंस शुल्क	<p>समझौते की अवधि के दौरान, प्रत्येक माह या उसके किसी भाग के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, (प्रसारणकर्ता का नाम) को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा जो वह दर होगी जिसे सब्सक्राइबर्स की औसत मासिक संख्या से गुणा करके निकाली जाएगी।</p> <p>प्रति सब्सक्राइबर ए-ला-कार्ट और बुके "दर" इस आरआईओ (RIO) के अनुलग्नक में दर्शाई गई है। इस आरआईओ के अनुलग्नक में उल्लिखित दरें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी करों और लेवी को छोड़कर हैं।</p> <p>"सब्सक्राइबर्स की औसत मासिक संख्या, विद्यार्थी माह के पहले और आखिरी दिन पर सब्सक्राइबर्स की संख्या को दो से भाग देकर प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर है।</p> <p>..... (प्रसारणकर्ता का नाम) को देय मासिक लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए किसी कलेंडर माह के लिए प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स हेतु "सब्सक्राइबर" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के माध्यम से (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनल प्राप्त कर रहा है।</p> <p>लाइसेंस फीस की गणना:</p> <p>I. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा (प्रसारणकर्ता का नाम) से एक या एक से अधिक बुके (बुके) प्राप्त करने के मामले में</p> <p>(क) यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपने सब्सक्राइबर्स को पूरा बुके (बुके) मुहैया करा रहा है तो ऐसे बुके (बुके) की मासिक लाइसेंस फीस, अनुलग्नक में दर्शाई गई बुके की दर को बुके (बुके) प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबर्स की मासिक औसत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर होगी।</p> <p>(ख) यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे चुना गया पूरा बुके (बुके) प्रदान नहीं करता है लेकिन ऐसे बुके या पैकेज में शामिल केवल कुछ चैनल प्रदान करता है तो इस तरीके से ऐसे चुने गए बुके में शामिल चैनलों के परिणामस्वरूप ऐसे चुने गए बुके में शामिल अलग-अलग चैनलों के लिए सब्सक्राइबर आधार भी अलग-अलग है तो ऐसी स्थिति में, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा ऐसे चुने गए पूरे बुके के लिए (प्रसारणकर्ता का नाम) को किए जाने वाले भुगतान की गणना उस चैनल के आधार पर की जाएगी जिसका सब्सक्राइबर आधार बुके में शामिल चैनलों के बीच सबसे अधिक है।</p> <p>II. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अ-ला-कार्ट आधार पर (प्रसारणकर्ता का नाम) के एक या एक से अधिक या सभी चैनलों को प्राप्त करने की स्थिति में</p> <p>(क) यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपने सब्सक्राइबर्स को अ-ला-कार्ट आधार पर चैनल मुहैया करा रहा है तो ऐसे अ-ला-कार्ट चैनलों के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क, अनुलग्नक में दर्शाई गई अ-ला कार्ट दर को अला कार्ट आधार पर चैनलों को प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबर्स की औसत मासिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर होगी।</p> <p>(ख) यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपने सब्सक्राइबर्स को अ-ला कार्ट आधार पर ऐसे चुने गए अला-कार्ट चैनल प्रदान नहीं करता है</p>
---------------	---

	<p>लेकिन ऐसे अला कार्टे चैनल के पैकेज में प्रदान करता है, तो प्रत्येक अ-ला कार्टे चैनल के लिए (प्रसारणकर्ता का नाम) को किए जाने वाले भुगतान की गणना पैकेज के सब्सक्राइबर आधार पर की जाएगी, जिसमें ऐसा चुना गया अला कार्टे चैनल रखा गया है।</p> <p>III यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (प्रसारणकर्ता का नाम) से अला कार्टे आधार पर एक या अधिक चैनल प्राप्त करता है और अला कार्टे आधार पर चुने गए चैनलों से अलग बुक (बुके) चुनता है तो:</p> <p>(क) बुक (बुके) के लिए लाइसेंस शुल्क की गणना ऊपर दिए गए उप-खंड I के आधार पर की जाएगी।</p> <p>(ख) अ-ला कार्टे चैनलों के लिए लाइसेंस शुल्क की गणना ऊपर दिए गए उप-खंड II के आधार पर की जाएगी।</p> <p>लाइसेंस शुल्क का भुगतान भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 और इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, रोके गए किसी कर/टीडीएस की कटौती के अध्वधीन होगा।</p>
भुगतान अवधि	<p>इस आरआईओ में यथा उल्लिखित रोके गए कर/टीडीएस को छोड़कर किसी अन्य कटौती के बिना (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत बिल प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर बकाया मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रत्येक माह के अंत में सात दिनों के अंदर उक्त माह के लिए सब्सक्राइबर्स की प्रारंभिक, अंतिम और औसत संख्या बताएगा, जिसके आधार पर, (प्रसारणकर्ता का नाम), मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को बिल प्रस्तुत करेगा। यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर उक्त सात दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजने में विफल रहता है तो (प्रसारणकर्ता का नाम) को अंतिम बिल प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को बाध्यता के तहत इस खंड की शर्तों के अनुसार उक्त अंतिम बिल के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना जरूरी होगा। बहरहाल, अंतिम बिल की राशि पिछले माह के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा देय मासिक लाइसेंस शुल्क से अधिक नहीं होगी। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्ष (पार्टी), (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आपस में मिलान करेगा।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए इससे संबंधित शर्तों के अनुसार, देय तारीख तक भुगतान करना जरूरी होगा, जिसमें विफल रहने पर इसे एतदधीन महत्वपूर्ण उलंघन माना जाएगा। विलंबित भुगतान पर % की मासिक दर से यथानुमान आधार पर ब्याज लिया जाएगा जिसकी गणना भुगतान की देय तिथि से पूर्ण भुगतान करने की तारीख तक के दिनों के लिए की जाएगी। विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाना और इसे एकत्रित करना, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को देय तिथि तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता है और इस समझौते के तहत (प्रसारणकर्ता का नाम) के अन्य अधिकार और प्रतिकार यथावत रहेंगे।</p> <p>इसमें आगे दिए गए लाइसेंस शुल्क में सभी और कोई सेवा कर, वैट, कार्य संविदा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क मनोरंजन कर, और ऐसे अन्य करों सहित लागू सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं हैं। ऐसे सभी कर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की लागत का हिस्सा होंगे और (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से प्रचलित दरों पर प्रभारित किए जाएंगे।</p> <p>यदि लाइसेंस शुल्क का भुगतान भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 और इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, रोके गए किसी कर/टीडीएस की कटौती के अध्वधीन है तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को उसके तहत जारी किए गए आय कर अधिनियम/नियमों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर (प्रसारणकर्ता का नाम) को कर</p>

	रोकने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
सुपुर्दगी और सुरक्षा	<p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सब्सक्राइबर्स को _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के सभी चैनलों की सुपुर्दगी इनमें कोई बदलाव किए बिना विश्वसनीय इन्क्रिप्टिड तरीके से करनी होगी।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अपने सब्सक्राइबर्स के दिए जा रहे _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनलों के प्रसारण सिगनल के संबंध में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा आवंटित अपलिक विशिष्टियां, सेटेलाइट क्षमता और इफ्रास्ट्रक्चर, इसके डिजिटल एंड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम प्लेटफार्म पर समान शैली के अंदर किसी अन्य चैनल के प्रसारण सिगनल से खराब नहीं होने चाहिए।</p>
एटी-पाइरेसी	<p>किसी चैनल की पूर्ण या आंशिक रूप से चोरी, पाइरेसी, अनाधिकृत पुनःप्रसारण, पुनर्वितरण या प्रदर्शन, नकल या डुप्लीकेशन (जिन्हें इसमें आगे सामुहिक रूप से "पाइरेसी" कहा जाएगा) पर रोक लगाने के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, समझौते की अवधि प्रारंभ होने से पहले और उक्त पूरी अवधि के दौरान, पूर्णतया प्रभावी कंडीशनल एक्सेस डिलिवरी और कटेड संरक्षण और सुरक्षा प्रणाली और संबंधित भौतिक सुरक्षा और परिचालनिक कार्यविधियों (जिन्हें इसमें आगे सामुहिक रूप से "सुरक्षा प्रणालियां" कहा गया है), _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा समय-समय पर लिखित में गैर-पक्षपाती तरीके से जैसे भी विनिर्दिष्ट (सुरक्षा विशिष्टियां) किए जाएं, का प्रयोग, रखरखाव और लागू करेगा।</p> <p>समझौते में उल्लिखित सुरक्षा नियमों का मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के लिए तकनीकी लेखा-परीक्षा ("तकनीकी लेखा-परीक्षा") करानी जरूरी होगी, जो _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा लिखित में अनुमोदित स्वतंत्र सुरक्षा टेक्नोलॉजी लेखा-परीक्षक (तकनीकी लेखा-परीक्षक) द्वारा की जाएगी और यह अवधि के दौरान वर्ष में दो बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसे _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) की लागत और खर्च पर कराया जाएगा। यदि तकनीकी लेखा-परीक्षा के परिणाम मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) में से किसी एक पक्ष द्वारा संतोषजनक नहीं पाए गए तो _____ (प्रसारणकर्ता का नाम), मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के साथ मिलकर इस समस्या को अगले 14 कार्यदिवसों में निपटाने के लिए कार्य करेगा। यदि वे इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) अपने स्वविवेक से मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के चैनल वितरण अधिकारों पर रोक लगा सकता है या समझौते की शर्तों के अनुसार अन्य कार्यवाही कर सकता है, ऐसी प्रणालियों, कार्यविधियों और सुरक्षा उपायों में _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) की संतुष्टि के अनुरूप सुधार होने तक यह सत्यापित करने के लिए कि प्रणालियों, कार्यविधियों और सुरक्षा उपायों में _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) की संतुष्टि के अनुरूप सुधार कर लिया गया है, इस संबंध में बाद में कराए गए किसी तकनीकी लेखा-परीक्षा की लागत और खर्च मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा वहन की जाएगी।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर 24 x 7 x 365(6) आधार पर कम से कम प्रत्येक 10 मिनट में अपने प्लेटफार्म के माध्यम से वितरित/प्रसारित चैनलों की पाइरेसी, कॉपीराइट के उलंघन, अप्राधिकृत रूप से देखने पर रोक लगाने के लिए एक फिंगर प्रिंटिंग प्रणाली लगाएगा।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर किसी भी चैनल के किसी भी हिस्से को रिकार्ड करने, डुप्लीकेट बनाने, केबलकास्ट करने, प्रदर्शन या चैनल उपलब्ध होने के समय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा वितरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुमति या इसे बाधित नहीं करने देगा। यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को पता चलता है कि कोई अप्राधिकृत तीसरा पक्ष किसी एक चैनल या सभी चैनलों की रिकार्डिंग, डुप्लीकेटिंग, केबल कास्टिंग, प्रदर्शन या किसी अन्य उद्देश्य से इनका इस्तेमाल कर रहा है तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर किसी एक</p>

	<p>चैनल या सभी चैनलों की रिकार्डिंग, डुप्लीकेटिंग, केबल कास्टिंग, प्रदर्शन या किसी अन्य उद्देश्य से इनका इस्तेमाल करने की जानकारी मिलते ही 10 मिनट के अंदर _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को सूचित करेगा और इस तरह के अप्राधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर संबंधित सेट टॉप बॉक्स को बंद कर देगा। बहरहाल, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत वीडियो रिकार्डर/डिजिटल वीडियो रिकार्डर की सुविधा वाले सेट टॉप बॉक्स का उपयोग अप्राधिकृत उपयोग नहीं माना जाएगा बशर्त कि सेट टॉप बॉक्स का उपयोग मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और सब्सक्राइबर के बीच हुए सब्सक्रिप्शन समझौते की शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप किया जाए।</p> <p>यदि _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) की सूचना (जैसा नीचे परिभाषित किया गया है) द्वारा इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर किसी ऐसे अप्राधिकृत सब्सक्राइबर/पाइरेसी में शामिल सब्सक्राइबर को _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) से ऐसा निर्देश प्राप्त होने के दस मिनट के अंदर शट ऑफ या आप्राधिकृत कर देगा। इस खंड के कोई भी संवाद/पत्र केवल तभी मान्य सूचना मानी जाएगी जब (i) सूचना प्लॉ की परस्पर सहमति वाले फॉर्मेट में ईमेल के जरिये भेजी जाए और (ii) सूचना ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के जरिये भेजी जाए जो इसके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। बहरहाल, _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के प्रतिनिधि द्वारा 'सूचना' संचार के अन्य साधन जैसे टेलीफोनिक संदेश, फैक्स आदि द्वारा भी भेजी जा सकती है और ऐसी 'सूचना' की मुष्टि _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा ईमेल के जरिये की जाएगी और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ऐसी सूचना के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।</p>
रिपोर्ट्स	<p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपने खर्च पर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली ("SMS") रखेगा जो पूर्णतया कैंस (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम) के तहत एकीकृत होगी।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनलों और टीयर और/या _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनल वाले पैकेज के लिए प्रारंभिक और अंतिम सब्सक्राइबरों की पूर्ण और सही मासिक रिपोर्ट _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा मुहैया कराए गए फॉर्मेट में प्रत्येक माह की समाप्ति से सात दिनों के अंदर _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को मुहैया करेगा।</p> <p>ऐसी रिपोर्ट्स में वे सभी सूचनाएं दी जाएंगी जो सब्सक्राइबरों की मासिक औसत संख्या (इसमें शामिल लेकिन प्रत्येक _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनल और प्रत्येक पैकेज, जिसमें _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनल शामिल हैं, के लिए सब्सक्राइबरों की संख्या तक सीमित नहीं है) और _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को देय लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए अपेक्षित होगी और ये विभागाध्यक्ष/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित होंगी, जो यह प्रमाणित करेगा कि रिपोर्ट में दी गई सभी सूचनाएं सत्य और सही हैं।</p>
लेखा-परीक्षा	<p>_____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के प्रतिनिधि को सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली, प्रसारणकर्ता द्वारा मुहैया कराए गए चैनल (चैनलों) के संबंध में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी अन्य प्रणालियों और रिकार्ड्स का एक साल में दो बार समीक्षा और/या लेखा-परीक्षा कराने का अधिकार है, इसका उद्देश्य _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को समझौते के अनुसार सही ढंग से देय राशि का भुगतान किया जा रहा है या नहीं और सब्सक्राइबर की रिपोर्ट में दी गई सूचना और समझौते की सभी शर्तों और निबंधनों के पूर्ण अनुपालन की जांच करना है। यदि ऐसी समीक्षा और या लेखा-परीक्षा में पता चलता है कि _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को अतिरिक्त शुल्क देय है तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर क्लिंबित भुगतान ब्याज दर</p>

	<p>से बड़े शुल्क के अनुसार उक्त शुल्क का तुरंत भुगतान करेगा। यदि किसी अवधि का देय शुल्क दो प्रतिशत या अधिक द्वारा ऐसी अवधि के लिए देय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा बताए गए शुल्क से अधिक है तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ऐसी समीक्षा और/या लेखा-परीक्षा के संबंध में _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करेगा और भविष्य में ऐसी गलती से बचने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर समझौते के अंतर्गत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा संकलित किए गए ग्रहकों के पूरे डाटाबेस का एकमात्र मालिक और धारक रहेगा।</p> <p>मल्टी सिस्टम ऑपरेटर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली ("SMS") को अपने खर्च पर रखेगा जो कम से कम निम्न में समर्थ हो</p> <p>(i) कंप्यूटरीकृत कस्टमर डाटाबेस बनाने के लिए प्रत्येक सब्सक्राइबर के नाम, पते, चुने गए भुगतान के तरीके और बिलिंग सहित पर्याप्त विवरण की रिकार्डिंग करने में समर्थ हो;</p> <p>(ii) नए सब्सक्राइबरों के लिए संविदा तैयार करके और वितरण करके एक इंफ्रस्ट्रक्चर, जिससे सतत संचालन के लिए एसएमएस डाटाबेस में सब्सक्राइबरों के कान्ट्रैक्ट एकत्रित और रिकार्ड किए जा सकें, की स्थापना और रखरखाव करके सब्सक्राइबरों के सब्सक्रिप्शन का प्रबंध करना;</p> <p>(iii) बिना लिमिटेशन, सब्सक्रिप्शन के भुगतान के बिलिंग और संग्रहण, क्रेडिट नियंत्रण, बिक्री संबंधी पूछताछ और शिकायतों के प्रबंध सहित सब्सक्राइबरों के संबंध में सतत प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना;</p> <p>(iv) सब्सक्राइबरों को प्रोग्रामिंग पैकेजों की बिक्री करने के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के अधिकृत एजेंटों को समय-समय पर देय किसी कमीशन शुल्क के भुगतान की व्यवस्था करना;</p> <p>(v) रीसिप्स और स्मार्टकार्ड, यदि लागू हो, प्राप्त करना और सब्सक्राइबरों को बांटना और अपने विवेक से समय-समय पर रिप्लेसमेंट स्मार्टकार्ड जारी करना; और</p> <p>(vi) ओवर-द-एयर एड्रेसिंग सिस्टम में एसएमएस के जरिये नए सब्सक्राइबरों को इनेबल करना और अपने विवेक से समय-समय पर चूककर्ता सब्सक्राइबरों को डिसेबल करना।</p>
अवधि	<p>यदि समझौते के अनुसार, अवधि पहले समाप्त नहीं हुई है तो समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष के अध्यक्षीन _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के बीच परस्पर सहमति वाली अवधि।</p> <p>पक्षों के बीच परस्पर सहमति लिखित में दर्ज शर्तों एवं निबंधनों और के आधार पर समझौते की अवधि बढ़ाई जा सकती है।</p>
समाप्त करना	<p>दोनों में से किसी भी पक्ष को लागू कानून के अधीन दूसरे पक्ष को लिखित में सूचना देकर निम्न स्थितियों में इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार है:</p> <p>1. दूसरे पक्ष द्वारा इस समझौते का महत्वपूर्ण उलंघन करना, जिसे लिखित में बताने के बावजूद तीस दिन के अंदर ठीक नहीं किया गया;</p>

	<p>2. दूसरे पक्ष दिवालियापन, ऋणशोधनक्षमता या उसकी परिसंपत्ति पर रिसीवर नियुक्त किया जाना;</p> <p>3. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को अपने डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम सेवा को चलाने के लिए आवश्यक डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम लाइसेंस या कोई दूसरा महत्वपूर्ण लाइसेंस को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की चूक से इतर किसी अन्य कारण से किसी भी समय रद्द किया गया है।</p> <p>_____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को निम्न स्थितियों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को लिखित में सूचना देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार है: (i) यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर किसी एंटी पाइरेसी शर्त का उलंघन करता है और लिखित में बताने के बावजूद 10 दिन के अंदर उसे ठीक करने में विफल रहता है; या</p> <p>(ii) _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) क्षेत्र के सभी वितरकों के संबंध में _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) के चैनल बंद कर देता है और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को कम से कम नब्बे दिन पूर्व इसकी सूचना दे देता है।</p> <p>यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अपना डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी सिस्टम बिजनेस बंद का देता है और कम से कम नब्बे दिन पूर्व इसकी सूचना दे देता है तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को _____ (प्रसारणकर्ता का नाम) को लिखित में सूचना देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।</p>
क्षेत्राधिकार	<p>इस पर लागू होने वाला कानून भारतीय कानून होगा और पक्षों के बीच समझौते के संबंध में और/या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई भी विवाद टीडीएसएटी के अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।</p>

(ख) बुके दरें

बुके - 1

चैनल	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए दर (रुपये)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

बुके 3

चैनल	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए दर (रुपये)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

बुके - 2

चैनल	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के लिए दर (रुपये)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

अनुसूची - III

अंतरासंघ समझौते के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा सिफोटिंग हेतु प्रोफार्मा, जो उनके तथा प्रसारणकर्ताओं और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के बीच निर्धारित किया गया है।

कॉलम →	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	क्र. सं.	समझौता करने वाले पक्षों के नाम	जिला, राज्य, पिन कोड और टेलीफोन नंबर सहित पक्ष का पूरा पता	कार्य का सेवा क्षेत्र	चैनलों की संख्या सहित बुक का नाम	बुके की दर	सब्सक्राइबर अथवा पिछले वर्ष १.01 जुलाई से लेकर चालू वर्ष के जून माह तक)	अ-ता-कॉर्ड चैनल का नाम और चैनलों की संख्या	अ-ता-कॉर्ड चैनल की दर

कॉलम →	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	घूट. यदि कोई है	सब्सक्राइबर अथवा पिछले वर्ष की जुलाई से लेकर चालू वर्ष के जून माह तक)	आईआरडी/वीवी संख्या-चैनल-चार	आईआरडी की अवधि	तारीख सहित समझौता संख्या	समझौता प्रारम्भ होने की तारीख	समझौता समाप्त होने की तारीख	प्रसारणकता द्वारा अदा किया गया कुल शुल्क है	टिप्पणी, यदि कोई है

व्याख्यात्मक ज्ञापन

I. पृष्ठभूमि

1. 10.12.2004 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(ट्राई) ने प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर के लिए लागू होने वाला एक अंतःसंयोजन विनियम बनाया। इस विनियम को "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13)" कहा गया था (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है)। इन विनियमों में 6 संशोधन किए जा चुके हैं।
2. मूल विनियम में अंतःसंयोजन के मामलों पर, मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराया गया है। विनियम में अंतःसंयोजन के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्थाओं और, सभी प्रसारण तथा केबल सेवाओं के लिए राजस्व हिस्सा कवर किया गया है। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं थीं: प्रसारकर्ताओं के लिए "अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए" (अर्थात् गैर-पक्षपातपूर्ण पहुंच) की व्यवस्था और "टीवी सिगनलों के डिसकनेक्शनों" की व्यवस्था। डिसकनेक्शन की नोटिस अवधि एक महीना थी। तथापि, यह व्यवस्था भी की गई थी कि सिगनलों के अनधिकृत रि-ट्रांसमिशन के मामले में नोटिस अवधि दो कार्य दिवस होंगे। डिसकनेक्शन के नोटिस में डिसकनेक्शन का कारण दिया जाना था। ऐसी स्थिति में डिसकनेक्शन का कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था, यदि सिगनलों के वितरण की अनुमति देने वाला कोई लिखित या मौखिक करार नहीं था। उपभोक्ताओं की सूचना के लिए यह व्यवस्था दी गई थी कि डिसकनेक्शन का नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए, जैसा कि विनियम में प्रावधान किया गया है। इन विनियमों में यह भी प्रावधान था कि प्रसारकों द्वारा अंतःसंयोजन प्रस्ताव एट्रेसेबल और गैर-एट्रेसेबल प्रणालियों के लिए आवश्यक है।
3. पिछले कुछ वर्षों में टीवी चैनलों (फ्री-टु-एयर और पे दोनों में) की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ एनालॉग केबल टीवी प्रणालियों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण भी केबल टीवी सेक्टर में अनेक चुनौतियां सामने आई हैं, मुख्यतः क्षमता संबंधी बाधाओं और नेटवर्क के एट्रेसेबल स्वरूप

के कारण। समय और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ नए एड्रसेबल डिजिटल टीवी मंच जैसे डीटीएच, आईपीटीवी आदि जनता को उपलब्ध हुए हैं। प्रौद्योगिक के विकास ने भी केबल टीवी सेक्टर में उपलब्धता के डिजिटाइजेशन लाने हेतु मार्ग प्रशस्त किया है। तदनुसार इस विषय का गहनता से अध्ययन करने और जिन परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात प्राधिकरण ने दिनांक 05 अगस्त, 2010 को इसे प्राप्त करने हेतु एक रोडमैप के साथ-साथ पूरे देश में डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों (डीएस) के कार्यान्वयन पर अपनी सिफारिशें दी थीं।

4. सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने का एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें भारत में डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन किया जा सके। इसके पश्चात सरकार ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें जून, 2012 से दिसंबर, 2014 तक चरणबद्ध तरीके से चार चरणों में कार्यान्वयन के लिए रोडमैप निर्धारित किया था। दिनांक 25 अक्टूबर 2011 का अध्यादेश बाद में दिसंबर 2011 में एक अधिनियम बन गया।

5. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के संशोधित उपबंधों और ऊपर उल्लिखित दिनांक 11/11/2011 की अधिसूचना पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की है। इस संबंध में "डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों" पर दिनांक 22/12/2011 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणालियों में अंतःसंयोजन के पहलू पर परामर्श के मुद्दे थे : मौजूदा अंतःसंयोजन विनियमों के संशोधनों पर सब्सक्राइबर्स के सुझाव, एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व के सब्सक्रिप्शन का हिस्सा, क्या "मस्ट कैरी" उपबंध, को एमएसओ के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्यों कैरिज शुल्क विनियमित किया जाना चाहिए और क्या डीएस क्षेत्रों के लिए लागू सेवा प्रदाताओं के बीच मानक अंतःसंयोजन करार विनिर्धारित किए जाने चाहिए। दिनांक 13 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी।

II. मुद्दों का विश्लेषण

6. मुख्य मुद्दों का सारांश, सब्सक्राइबर्स की टिप्पणियां और उन पर विश्लेषण निम्नलिखित है:

टिप्पणी : संदर्भ की आसानी के लिए और सभी सब्सक्राइबर्स द्वारा इसे समझने में सुविधाजनक बनाने हेतु मौजूदा विनियमों में सभी पिछले अंतःसंयोजन विनियमों का समेकन किया जा रहा है और अब बनाए जा रहे विनियमों को डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली के लिए लागू किया जा रहा है।

ए. अंतःसंयोजन विनियमों में प्रस्तावित संशोधन

विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या अंतःसंयोजन विनियमों के किसी मौजूदा खंड में संशोधन की आवश्यकता है।

7. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्रसारणकर्ताओं/एग्रीगेटरों ने मौजूदा अंतःसंयोजन विनियमों के कुछ खंडों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया जैसे सिग्नल के डिसकनेक्शन के लिए नोटिस अवधि कम करना, सेवा प्रदाता की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) की लेखा-परीक्षा करने की प्रक्रिया, तकनीकी पक्ष पर — एसएमएस और कंडीशनल एक्सेस प्रणाली (सीएस) के एकीकरण के उपबंध बनाना ताकि प्रणाली की पूर्ण एड्रेसेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। यह भी सुझाव दिया गया कि विनियम में एंटी-पाइरेसी और फिंगरप्रिंटिंग के उपबंध किए जाएं तथा एमएसओ/एलसीओ द्वारा अंतःसंयोजन करार करने के और अभिदान के लिए न्यूनतम अवधि के लिए उपबंध बनाए जाएं। यह भी सुझाव दिया गया कि "उपलब्ध कराया जाना चाहिए" से संबंधित दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 के खंड 3.2 को भी उन सेवा प्रदाताओं के मामले में इसे लागू करके अर्हक बनाया जा सकता है, जो विनियमों में से किसी विनियम का अनुपालन करने में विफल रहे हैं। हितधारकों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि मौजूदा अंतःसंयोजन विनियम में कुछ परिभाषाओं में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें 2011 में यथासंशोधित केबल टेलीविजन अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। कुछ एमएसओ ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वे मौजूदा खंडों में किसी संशोधन के पक्ष में नहीं हैं। कुछ एलसीओ ने सुझाव दिया है कि डिसकनेक्शन नोटिस, राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के संबंध में अंतःसंयोजन विनियमों के खंडों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

8. एमएसओ द्वारा अंतःसंयोजन करारों दायर करने के मुद्दे पर प्राधिकरण ने इस सुझाव पर विचार किया और निर्णय लिया कि इस विनियम में इस संबंध में एक उपबंध शामिल किया जाए ताकि प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके। प्रसारणकर्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले कैरिज शुल्कों के ब्योरो के साथ-साथ एमएसओ द्वारा अंतःसंयोजन करारों के ब्योरो की रिपोर्टिंग के लिए इस विनियम में उपबंध किया गया है। प्रसारणकर्ताओं के लिए रिपोर्टिंग संबंधी शर्त भी उनके लिए इस बात को अनिवार्य बनाती है कि वे उनके द्वारा भुगतान किए गए कैरिज शुल्क के ब्योरे दाखिल करें। परिभाषाओं में संशोधन करने के मुद्दे पर "एड्रेसेबल प्रणाली", "प्रसारणकर्ता", "केबल ऑपरेटर", "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर", "पे चैनल" और "सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली" जैसी परिभाषाओं को संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के अनुरूप बनाया गया है। अभिदान की न्यूनतम अवधि के मुद्दे के संबंध में दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी क्षेत्र) टैरिफ आदेश, 2012 में प्रावधान किया गया है। डिसकनेक्शन के लिए नोटिस अवधि के मुद्दे पर प्राधिकरण ने इस तथ्य पर विचार किया कि नोटिस अवधि, हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मंच से अनुरोध करने तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक मंच से अनुरोध करने का अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाने हेतु प्रभावित पक्षों को दी जाने वाली नोटिस अवधि पर्याप्त होनी चाहिए। इसलिए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 21 दिनों की नोटिस की मौजूदा अवधि को बनाए रखा जाए। एसएमएस की लेखापरीक्षा के सुझाव पर प्राधिकरण ने इस तथ्य पर विचार किया कि अंतःसंयोजन विनियमों के मौजूदा उपबंधों में एक कैलेंडर वर्ष में दो लेखापरीक्षाएं तक करने का उपबंध है। प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि लेखापरीक्षा के लिए यह पर्याप्त अवसर है और इसलिए निर्णय लिया कि इस संबंध में मौजूदा उपबंधों में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। एसएमएस और सीएस के एकीकरण के मुद्दे पर प्राधिकरण ने पाया कि मौजूदा अंतःसंयोजन फ्रेमवर्क में दोनों प्रणालियों के जरिए साथ-साथ किए जाने वाले एसएमएस से एक्टिवेशन और डिएक्टिवेशन प्रक्रिया के लिए एसएमएस और सीएस प्रणाली के एकीकरण का प्रावधान है। प्राधिकरण का विचार है कि यह उपबंध पर्याप्त है और इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। एंटी-पाइरेसी और फिंगरप्रिंटिंग के मुद्दे पर प्राधिकरण ने पाया कि मौजूदा फ्रेमवर्क में यह उपबंध है कि ऑपरेटर एंटी-पाइरेसी का पता लगाने, कॉपीराइट के उल्लंघन और अपने मंच के जरिए प्रसारित, वितरित/ ट्रांसमिटिड चैनलों को अनधिकृत रूप से देखने का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंटिंग तंत्र बनाए। प्राधिकरण का विचार है कि यह उपबंध पर्याप्त है और इसलिए इस मुद्दे पर

किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अवश्य "उपलब्ध कराया जाना चाहिए" के मुद्दे पर विनियमों के उल्लंघन पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्राधिकरण का विचार है कि इस उपबंध में किसी अन्य अर्हता की आवश्यकता नहीं है।

बी. "मस्ट कैरी" उपबंध

9. मुद्दा यह है कि क्या "मस्ट कैरी" उपबंध, एमएसओ के लिए अनिवार्य होना चाहिए, यदि हां तो किस अर्हक शर्त पर और किस तरीके से किसी एमएसओ को, टीवी चैनल के कैरिज के लिए अपने नेटवर्क को पहुंच का प्रस्ताव देना चाहिए। अधिकांश प्रसारणकर्ता इस पक्ष में हैं कि मौजूदा अंतःसंयोजन विनियमों में विनिर्धारित "मस्ट कैरी" खंड को संतुलित करने के लिए "मस्ट कैरी" उपबंध को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि नेटवर्क एक्सेस करने का तरीका गैर-पक्षपात आधार पर होना चाहिए और अर्हक शर्तों में लेखा-परीक्षा और पारदर्शिता, चैनलों का गैर-पक्षपातपूर्ण सूचीकरण शामिल किया जा सकता है और चैनल, एमएसओ की ईपीजी में श्रेणीवार होने चाहिए। एक प्रसारणकर्ता ने यह भी सुझाव दिया है कि "मस्ट कैरी" उपबंध को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
10. अधिकांश एमएसओ और एलसीओ ने सुझाव दिया कि कोई "मस्ट कैरी" उपबंध नहीं होना चाहिए। उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि यह केवल डीडी चैनलों के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसे कार्यान्वित करने के तरीके के संबंध में एक एलसीओ ने सुझाव दिया कि दूरदर्शन चैनलों को छोड़कर सभी के लिए "मस्ट कैरी" चैनलों के लिए कैरिज शुल्क अर्हक शर्त होनी चाहिए। कुछ एलसीओ ने "मस्ट कैरी" उपबंध का समर्थन किया और कहा कि यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होना चाहिए। अन्य स्टैकहोल्डर जिन्होंने अपनी टिप्पणियां दीं, "मस्ट कैरी" उपबंध के पक्ष में नहीं थे।
11. प्राधिकरण का यह विचार है कि डिजिटल ट्रांसमिशन वातावरण में, चैनल चलाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। डिजिटल वातावरण में सब्सक्राइबर को एक मुख्य लाभ एमएसओ के चैनल वहन करने की क्षमता के अनुसार चैनलों की बड़ी संख्या में उपलब्धता है। बहरहाल, चैनल वहन करने की लागत का तत्व होता है। यदि ऑपरेटर की चैनल वहन करने की लागत (कैरिज शुल्क) के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है तो चैनल वहन करने के लिए कोई प्रौद्योगिकीय अथवा अन्य अवसंरचनात्मक कठिनाई नहीं होगी।

एड्रेसेबल प्रणालियों में, सब्सक्राइबर्स की संख्या का पता लगाने में पारदर्शिता होने के कारण सब्सक्रिप्शन राजस्व बढ़ने की संभावना है। अतः राजस्व के रूप में एमएसओ की कैरिज शुल्क पर निर्भरता कम होने की संभावना है। इन तथ्यों को देखते हुए प्राधिकरण का विचार है कि यह एमएसओ पर छोड़ दिया जाए कि वह कैरिज शुल्क की राशि का निर्णय स्वयं करे। बहरहाल, इस विनियम में एमएसओ के नेटवर्क के साथ बिना भेदभाव एक्सेस प्राप्त करने के लिए एमएसओ के संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कैरिज शुल्क की घोषणा करने तथा प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रावधान किया गया है। आगे, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2012 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण मस्टी सिस्टम ऑपरेटर की चैनल कैरी करने की क्षमता का निर्धारण करेगा।

12. वर्तमान परामर्श प्रक्रिया के लिए किए गए विश्लेषण (इस व्याख्यात्मक ड्रापन के साथ संलग्न अनुबंध-ए) ने यह दर्शाया है कि राज्यवार तथा संघशासित राज्य व चैनलों की अधिकतम संख्या, किसी राज्य अथवा संघशासित राज्य से संबंधित संगत भाषावार चैनल, जिन्हें केबल टीवी नेटवर्क पर चलाया जा सकता है में से प्रचालनरत 650 निजी चैनल (अप्रैल, 2012 की स्थिति), जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा [अपलिकिंग/डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान किए गए 831 चैनलों (06 मार्च, 2012 की स्थिति) में से] डाउनलिकिंग की अनुमति प्रदान की गई है तथा राष्ट्रीय पब्लिक ब्रॉडकास्टर (प्रसार भारती) के 18 चैनल तथा लोकसभा चैनल (कुल 19 चैनल में से) 473 चैनल आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दिनांक 11.01.2013 वह तारीख जिससे खंड 3.8 (मस्ट कैरी) के उपबंध लागू हो जाएंगे, तक कुछ चैनल प्रचालनरत हो जाएंगे, यह बात तर्कसंगत है कि उन चैनलों की अधिकतम संख्या, जो डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली नेटवर्क में चलाए जा सकते हैं, 500 चैनल हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि दो प्रकार के एमएसओ होते हैं। बड़े आकार के एमएसओ, जिनके पास 25,000 से ज्यादा और लाखों की संख्या तक सब्सक्राइबर होते हैं और छोटे सब्सक्राइबर जिनके पास लगभग 25,000 या उससे कम के सब्सक्राइबर होते हैं। प्रचालन के बड़े आकार के कारण बड़े आकार के कारण बड़े आकार के एमएसओ के पास छोटे आकार के एमएसओ की तुलना में कम क्षमता होती है। अतः छोटे एमएसओ को प्रति हैडएंड 500 चैनल की क्षमता सृजित करने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया है और बड़े आकार के एमएसओ के लिए यह समय 01 जनवरी, 2013 रखा गया है। बहरहाल, यह देखते हुए कि दिल्ली, मुंबई,

कोलकाता और चेन्नई, चार महानगरों में 01 जुलाई, 2012 से डिजिटल व्यवस्था लागू की जानी है और अधिकांश एमएसओ पहली बार में उस तारीख तक प्रति हेडएंड कम से कम 500 चैनल चलाने की क्षमता सृजित करने में समर्थ नहीं होंगे इसलिए उन्हें प्रति हेडएंड 200 चैनल की न्यूनतम क्षमता के साथ प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस विनियम में की गए प्रावधानों के अनुसार जैसे कि एमएसओ को धीरे-धीरे अपनी क्षमता बढ़ाकर 01 अप्रैल, 2013 तक प्रति हेडएंड कम से कम 500 चैनल चलाने की क्षमता सृजित करना है। इसलिए ऐसे सभी एमएसओ के पास प्रति हेडएंड कम से कम 500 चैनल चलाने की क्षमता होना अपेक्षित है।

13. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को, अपने केबल नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करने के लिए, विनियमों में 60 दिन की समय-सीमा प्रदान की गई है जो "मस्ट प्रोवाइड" उपबंधों के अंतर्गत प्रसारणकर्ता को दी गई समय-सीमा के समतुल्य है। किसी भी स्थिति में यह समय-सीमा उस अनुरोध जिसमें ऑपरेटर के नेटवर्क एक्सेस करने की मांग की गई है, की तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. "मस्ट कैरी" प्रावधान के अंतर्गत ब्रॉडकास्टर अथवा एमएसओ के केबल नेटवर्क से एक्सेस प्राप्त करने के इच्छुक पर भी जिम्मेवारी डाली गई है। कि वह पिछले 6 महीने के सब्सक्राइबर आधार के औसत के रूप में लिए गए कम से कम उस एमएसओ के सब्सक्राइबर आधार के पांच प्रतिशत से ज्यादा अथवा उसके बराबर का सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करे। यदि वह इस सब्सक्रिप्शन आधार को बनाए रखने में विफल रहता है तो नेटवर्क प्रदाता अपने विवेकानुसार अगले एक वर्ष के लिए नेटवर्क की आगे एक्सेस के लिए मान कर सकता है। इस प्रकार की मनाही "मस्ट कैरी" प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

सी. "कैरिज शुल्क"

15. मुद्दा यह है कि क्या कैरिज शुल्क को विनियमित किया जाना चाहिए, यदि हां तो क्या इसकी मात्रा को किसी पैरामीटर से जोड़ा जाना चाहिए। समाचार प्रसारणकर्ता संघ का विचार है कि कैरिज शुल्क विनियमित किया जाना चाहिए। इस संघ का विचार है कि यदि "मस्ट कैरी" उपबंध को अनिवार्य बनाया जाता है तो कैरिज शुल्क का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अधिकांश प्रसारणकर्ता और प्रसारणकर्ताओं का एक संघ, कैरिज शुल्क को विनियमित करने के पक्ष में नहीं है और उन्होंने सुझाव

दिया है कि यह प्रसारणकर्ता और एमएसओ के बीच परस्पर वार्ता पर आधारित होना चाहिए। कुछ जो इसके पक्ष में थे, ने सुझाव दिया कि पैरामीटर, एमएसओ का सब्सक्राइबर आधार, संस्थापित एसटीबी की संख्या आदि हो सकते हैं। एक ब्रॉडकास्टर में एक ने सुझाव दिया कि कैरिज शुल्क, "मस्ट कैरी" अनिवार्य खंड के अंतर्गत कवर न किए गए चैनलों के लिए एकत्र किए गए अभिदान शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

16. एमएसओ, कैरिज शुल्क पर किसी प्रकार के विनियामक हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं। अधिकांश एलसीओ, कैरिज शुल्क को विनियमित करने के पक्ष में नहीं हैं। कुछ एलसीओ ने सुझाव दिया कि कैरिज शुल्क को विनियमित किया जाना चाहिए और इसे संस्थापित एसटीबी के संख्या, अभिदान राशि के सकल संग्रहण और नेटवर्क के आकार तथा स्थान आदि के साथ संबद्ध किया जा सकता है। कुछ एलसीओ का सुझाव है कि एलसीओ को भी कैरिज शुल्क से एक भाग प्राप्त होना चाहिए।

17. एड्रिसेबल प्रणालियों में पारदर्शिता होने के कारण यह आशा की जाती है कि सब्सक्रिप्शन राजस्व में वृद्धि होगी और इसलिए एमएसओ की निर्भरता कैरिज शुल्क पर कम हो जाएगी। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्राधिकरण का मत है कि कैरिज शुल्क को विनियमित करने की आवश्यकता है। इसलिए निम्नलिखित योजना कार्यान्वित की गई है। जो एमएसओ टीवी चैनलों को कैरी करने के लिए कैरिज शुल्क चार्ज करते हैं उन्हें इस शुल्क के बारे में घोषणा करनी है, इसके अलावा कैरिज शुल्क बिना भेदभाव के पारदर्शी रूप में लिया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि कैरिज शुल्क में कम से कम दो वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं होगी और इस शुल्क का विवरण प्राधिकरण को दिया जाएगा। प्राधिकरण यदि उचित समझता है तो वह हस्तक्षेप कर सकता है और कैरिज शुल्क में उचित परिवर्तन के लिए कह सकता है।

डी. मानक अंतःसंयोजन करार (एसआईए)

18. मुद्दा यह है कि क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं के बीच एक मानक अंतःसंयोजन करार निर्धारित करे। लगभग आधे प्रसारणकर्ता जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां दीं, प्राधिकरण द्वारा एसआईए निर्धारित करने के पक्ष में नहीं हैं जबकि अन्य प्राधिकरण द्वारा एसआईए

निर्धारित करने के पक्ष में हैं। जो इसके पक्ष में थे, उन्होंने सुझाव दिया कि पाइरेसी और परिसमापन खंड की समीक्षा की जानी चाहिए।

19. एक एमएसओ को छोड़कर जिसने सुझाव दिया कि आरआईओ आधारित तंत्र ने डीटीएच सेक्टर के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए इसका विस्तार डीएस के लिए किया जाना चाहिए, अन्य एमएसओ, प्राधिकरण द्वारा एसआईए निर्धारित करने के पक्ष में हैं। अधिकांश एलसीओ, एसआईए के पक्ष में हैं जबकि उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि एसआईए की कोई तुरंत आवश्यकता नहीं है। अन्य स्टेकहोल्डरों जिन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, प्राधिकरण द्वारा एसआईए निर्धारित करने के पक्ष में हैं।

20. प्राधिकरण का विचार है कि चूंकि अंतःसंयोजन विनियमों में पहले ही, आरआईओ के रूप में एड्रसेबल प्रणालियों के लिए आवश्यक विनियामक ढांचे का उपबंध है, जो वर्ष 2006 में नहीं का, जब कैस के लिए एसआईए निर्धारित किया गया था, इसलिए डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली में एमएसओ तथा एलसीओ के बीच और प्रसारणकर्ता तथा एमएसओ के बीच मानक अंतःसंयोजन करार निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण का विचार है कि आरआईओ आधारित निर्धारित व्यवस्था, डीएस में लागू रहना चाहिए।

ई. विज्ञापन मुक्त (एड फ्री) चैनल

21. मुद्दा यह है कि विज्ञापन मुक्त चैनलों के संबंध में अंतःसंयोजन विनियमों में क्या उपबंध होने चाहिए और इन चैनलों के संबंध में प्रसारणकर्ताओं और वितरकों के बीच राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था क्या होनी चाहिए। कुछ प्रसारणकर्ताओं और एमएसओ ने कहा कि अंतःसंयोजन विनियमों की मौजूदा अपेक्षा/शर्त अर्थात् "मस्ट प्रोवाइड" विज्ञापनमुक्त चैनलों पर लागू नहीं होनी चाहिए और प्रसारणकर्ता तथा संबंधित सेवा प्रदाता, परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर करार करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए ताकि नए अभिनव और गैर-जन बाजार विज्ञापन आधारित टेलीविजन घटक सृजित करने, विकसित करने और विपणन करने हेतु मूल्य श्रृंखला में सभी को प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सके। अन्य स्टेकहोल्डरों में से अधिकांश जिन्होंने इस मुद्दे पर प्रत्युत्तर दिया, कहते हैं कि मौजूदा अंतःसंयोजन विनियम, विज्ञापनमुक्त चैनलों पर भी लागू होने चाहिए ताकि उपभोक्ता इन चैनलों से वंचित न रहें। कुछ केबल ऑपरेटरों का विचार है कि अधिसूचित कैस क्षेत्रों पर लागू होने वाले अंतःसंयोजन विनियमों के उपबंध, विज्ञापनमुक्त

चैनलों पर लागू होने चाहिए। जहां तक विज्ञापनमुक्त चैनलों के अभिदान राजस्व की हिस्सेदारी का संबंध है, सभी प्रसारणकर्ताओं ने राय व्यक्त की है कि इसे सेवा प्रदाताओं के बीच वाणिज्यिक बातचीत पर छोड़ा जाना चाहिए। कुछ अन्य स्टेकहोल्डरों ने सुझाव दिया कि राजस्व हिस्सा उसी तरीके से तय किया जाए जैसे किसी अन्य भुगतान चैनल के मामले में किया जाता है, जबकि अन्य ने प्रसारणकर्ता, एमएसओ और एलएसओ के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत का सुझाव दिया, परंतु उन्होंने इस सुझाव के लिए कोई औचित्य नहीं दिया।

22. विज्ञापनमुक्त चैनलों की दरों और इन चैनलों के अभिदान राजस्वों की हिस्सेदारी के मुद्दे पर, दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रसेबल प्रणालियां) टैरिफ (पहला संशोधन) आदेश, 2012 के उपबंधों में अलग से चर्चा की गई है। प्राधिकरण का मत है कि आज की प्रचलित नीति के अनुसार इनको बाजार की शक्तियों द्वारा तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एमएसओ को प्रसारणकर्ता द्वारा चैनलों के सिगनलों से मना करने या चैनल चलाने से एमएसओ द्वारा मना करने से रोकने के लिए इन चैनलों को, अंतःसंयोजन विनियमों के खंड "मस्ट प्रोवाइड" और "मस्ट कैरी" के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा।

अनुलग्नक-क

राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार/भाषा-वार टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या जो डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रचालनरत 650 निजी चैनलों में से केबल टीवी नेटवर्क पर दिखाए जा सकते हैं (अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार डाटा)			
क्र. सं.	राज्य	चैनलों की संख्या	भाषाएं
1	आन्ध्र प्रदेश	473	हिंदी/अंग्रेजी/तेलुगु+19 चैनल*
2	अरुणाचल प्रदेश	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
3	असम	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
4	बिहार	428	हिंदी/अंग्रेजी/भोजपुरी+19 चैनल
5	छत्तीसगढ़	420	हिंदी/अंग्रेजी+19 चैनल
6	गोवा	438	हिंदी/अंग्रेजी/मराठी+19 चैनल
7	गुजरात	428	हिंदी/अंग्रेजी/गुजराती+19 चैनल
8	हरियाणा	441	हिंदी/अंग्रेजी/पंजाबी+19 चैनल
9	हिमाचल प्रदेश	441	हिंदी/अंग्रेजी/पंजाबी+19 चैनल
10	जम्मू एवं कश्मीर	424	हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू+19 चैनल

11	झारखण्ड	428	हिंदी/अंग्रेजी/भोजपुरी+19 चैनल
12	कर्नाटक	437	हिंदी/अंग्रेजी/कन्नड़+19 चैनल
13	केरल	451	हिंदी/अंग्रेजी/मलयालम+19 चैनल
14	मध्य प्रदेश	420	हिंदी/अंग्रेजी+19 चैनल
15	महाराष्ट्र	438	हिंदी/अंग्रेजी/मराठी+19 चैनल
16	मणिपुर	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
17	मेघालय	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
18	मिजोरम	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
19	नागालैंड	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
20	ओडिशा	434	हिंदी/अंग्रेजी/उड़िया +19 चैनल
21	पंजाब	441	हिंदी/अंग्रेजी/पंजाबी+19 चैनल
22	राजस्थान	420	हिंदी/अंग्रेजी +19 चैनल
23	सिक्किम	446	हिंदी/अंग्रेजी/बंगाली +19 चैनल
24	तमिलनाडु	462	हिंदी/अंग्रेजी/तमिल+19 चैनल
25	त्रिपुरा	425	हिंदी/अंग्रेजी/एनई एवं असमी+19 चैनल
26	उत्तराखण्ड	424	हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू+19 चैनल
27	उत्तर प्रदेश	424	हिंदी/अंग्रेजी/उर्दू+19 चैनल
28	पश्चिम बंगाल	446	हिंदी/अंग्रेजी/बंगाली 19 चैनल
29	अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह	420	हिंदी/अंग्रेजी+19 चैनल
30	दादर और नागर हवेली	420	हिंदी/अंग्रेजी+19 चैनल
31	दमन एवं दीव	420	हिंदी/अंग्रेजी+19 चैनल
32	लक्षद्वीप	420	हिंदी/अंग्रेजी+19 चैनल

33	दिल्ली	441	हिंदी/अंग्रेजी/पंजाबी+19 चैनल
34	चंडीगढ़	441	हिंदी/अंग्रेजी/पंजाबी+19 चैनल
35	पांडिचेरी	441	हिंदी/अंग्रेजी/तमिल/फ्रेंच +19 चैनल

*19 चैनलों में 8 वे चैनल शामिल हैं जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना अपेक्षित है और 11 क्षेत्रीय प्रसार भारती (दूरदर्शन) चैनल हैं।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2012

F. No. 3-24/2012-B & CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,-----

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and

(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES) INTERCONNECTION (DIGITAL ADDRESSABLE CABLE TELEVISION SYSTEMS) REGULATIONS, 2012

No. 9 of 2012

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires : -

- (a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 (24 of 1997);
- (b) "addressable system" means an electronic device (which includes hardware and its associated software) or more than one electronic device put in an integrated system through which signals of cable television network can be sent in encrypted form, which can be decoded by the device or devices, having an activated Conditional Access System at the premises of the subscriber within the limits of authorisation made, through the Conditional Access System and the subscriber management system, on the explicit choice and request of such subscriber, by the cable operator to the subscriber;
- (c) "agent or intermediary" means any person including an individual, group of persons, public or body corporate, firm or any organization or body authorised by a broadcaster/ multi system operator to make available TV channel/s, to a distributor of TV channels;
- (d) "a-la-carte" with reference to offering of a TV channel means offering the channel individually on a standalone basis;
- (e) "a-la-carte rate" means the rate at which a standalone individual channel is offered to the distributor of TV channels or to the subscriber, as the case may be;
- (f) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997;

(g) "broadcaster" means a person or a group of persons, or body corporate, or any organisation or body providing programming services and includes his or its authorised distribution agencies;

(h) "broadcasting services" means the dissemination of any form of communication such as signs, signals, writing, pictures, images and sounds of all kinds by transmission of electro magnetic waves through space or through cables intended to be received by the general public either directly or indirectly and all its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;

(i) "bouquet" or "bouquet of channels" means an assortment of distinct channels, offered together as a group or as a bundle;

(j) "bouquet rate" or "rate of bouquet" means the rate at which a bouquet of channels is offered to the distributor of TV channels or to the subscriber, as the case may be;

(k) "cable operator" means any person who provides cable service through a cable television network or otherwise controls or is responsible for the management and operation of a cable television network and fulfils the prescribed eligibility criteria and conditions;

(l) "cable service" means the transmission by cables of programmes including re-transmission by cables of any broadcast television signals;

(m) "cable television network" means any system consisting of a set of closed transmission, paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;

(n) "carriage fee" means any fee paid by a broadcaster to a distributor of TV channels, for carriage of the channels or bouquets of channels of that broadcaster on the distribution platform owned or operated by such distributor of TV channels, without specifying the placement of various channels of the broadcaster vis-a-vis channels of other broadcasters;

- (o) "commercial subscriber" means any subscriber who receives a programming service at a place indicated by him to a service provider and uses signals of such service for the benefit of his clients, customers, members or any other class or group of persons having access to such place;
- (p) "DAS area" means the areas where in terms of notifications issued by the Central Government under sub-section (1) of section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), it is obligatory for every cable operator to transmit or re-transmit programmes of any channel in an encrypted form through a digital addressable system;
- (q) "distributor of TV channels" means any person including an individual, group of persons, public or body corporate, firm or any organization or body re-transmitting TV channels through electromagnetic waves through cable or through space intended to be received by general public directly or indirectly and such person may include, but is not limited to a multi system operator;
- (r) "free-to-air channel", in respect of a cable television network, means a channel for which no subscription fee is to be paid by the cable operator to the broadcaster for its re-transmission on cable;
- (s) "Multi-System Operator" means a cable operator who has been granted registration under rule 11C of the Cable Television Networks Rules, 1994, and who receives a programming service from a broadcaster or its authorised agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators and includes his authorised distribution agencies, by whatever name called;
- (t) "ordinary subscriber" means any subscriber who receives a programming service from a multi system operator directly or through his linked local cable operator and uses the same for his domestic purposes;

- (u) "pay channel", in respect of a cable television network, means a channel for which subscription fees is to be paid to the broadcaster by the cable operator and due authorisation needs to be taken from the broadcaster for its re-transmission on cable;
- (v) "placement fee" means any fee paid by a broadcaster to a distributor of TV channels, for placement of the channels of such broadcaster vis-à-vis channels of other broadcasters on the distribution platform owned or operated by such distributor of TV channels;
- (w) "programme" means any television broadcast and includes-
- (i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials through video cassette recorders or video cassette players;
 - (ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation
- and the expression "programming service" shall be construed accordingly;
- (x) "RIO" means the Reference Interconnect Offer published by a service provider specifying terms and conditions on which other service provider may seek interconnection from the service provider making the offer;
- (y) "service provider" means the Government as a service provider and includes a licensee as well as any broadcaster, multi system operator, cable operator or distributor of TV Channels;
- (z) "set top box" means a device, which is connected to, or is part of a television and which allows a subscriber to receive in unencrypted and descrambled form subscribed channels through an addressable system;
- (za) "subscriber" means a person who receives the signals of a service provider at a place indicated by him to the service provider without further transmitting it to any other person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers unless specifically excluded;
- (zb) "subscriber base" means the number of subscribers reflected in the subscriber management system, of the digital addressable systems;
- (zc) "subscriber management system" means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the

hardware being utilised by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed to by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber's record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;

(zd) "TV channel" means a channel, which has been registered under -----

(i) the guidelines for uplinking from India, issued vide No.1501/2/2002-TV(I)(Pt.) dated the 2nd December, 2005; or

(ii) policy guidelines for downlinking of televisions channels, issued vide No. 13/2/2002-BP&L/BC-IV dated the 11th November, 2005, -----

as amended from time to time, or such other guidelines for uplinking or downlinking of television channels, as may be issued from time to time by Government of India (Ministry of Information and Broadcasting) and reference to the term 'channel' shall be construed as a reference to "TV channel";

(ze) all other words and expressions used in this regulations but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made thereunder or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) and the rules and regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

CHAPTER - II

INTERCONNECTION

3. General Provisions relating to interconnection.-(1) No broadcaster of TV channels shall engage in any practice or activity or enter into any understanding or arrangement, including exclusive contract with any multi system operator for distribution of its channel which may prevent any other multi system operator from obtaining such TV channels for distribution.

(2) Every broadcaster shall provide signals of its TV channels on non-discriminatory basis to every multi system operator having the prescribed channel capacity and registered under rule 11 of the Cable Television Networks Rules, 1994, making request for the same.

Provided that nothing contained in this sub-regulation shall apply in the case of a multi system operator who is in default of payment.

Provided further that imposition of any term which is unreasonable shall be deemed as a denial of request.

(3) Every broadcaster or his authorized agent shall provide the signals of TV channels to a multi system operator, in accordance with its reference interconnect offer or as may be mutually agreed, within sixty days from the date of receipt of the request and in case the request for providing signals of TV Channels is not agreed to, the reasons for such refusal to provide signals shall be conveyed to the person making a request within sixty days from the date of request.

(4) Every multi system operator while seeking interconnection with the broadcaster, shall ensure that its digital addressable system installed for the distribution of TV channels meets the digital addressable system requirements specified in Schedule 1 to these regulations:

Provided that in case the broadcaster finds that the digital addressable system being used by the multi system operator for distribution of TV channel does not meet the requirements

specified in the Schedule I, it shall inform such multi system operator who shall get its digital addressable system audited by M/s. Broadcast Engineering Consultants India Ltd., or any other agency as may be specified by the Authority by direction issued from time to time and obtain a certificate from such agency that its system meets the requirements specified in Schedule I to these regulations :

Provided further that the findings of the agency referred to in the first proviso shall be final.

(5) A multi system operator, who seeks signals of a particular TV channel from a broadcaster, shall not demand carriage fee for carrying that channel on its distribution platform.

(6) If a broadcaster before providing signals to a multi system operator insist for placement of its channel in a particular slot as a pre-condition for providing signals, such pre-condition shall amount to imposition of unreasonable terms.

(7) Every broadcaster or his authorised agent who collects payment on behalf of such broadcaster, shall issue monthly invoice to the multi system operator for providing signals to the multi system operator and such invoice/s shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date for payment.

(8) Every multi system operator, operating in the areas notified by the Central Government under sub-section (1) of the section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, shall have the capacity to carry a minimum of five hundred channels not later than the date mentioned in the said notification applicable to area in which the multi system operator is operating.

Provided that a multi system operator operating in the Municipal boundary of Greater Mumbai, National Capital Territory of Delhi, Kolkata Metropolitan area and Chennai Metropolitan area shall have a capacity to carry a minimum of two hundred channels as on the 30th June, 2012 and such capacity shall be enhanced to a minimum of five hundred channels by 1st January, 2013:

Provided further that all multi system operators operating in the area referred to in the first proviso and having subscriber base of less than twenty five thousand shall have the capacity to carry a minimum of five hundred channels by the 1st April, 2013.

(9) No multi system operator shall enter into any understanding or arrangement with any broadcaster that may prevent any other broadcaster from obtaining access to the cable network of such multi system operator.

(10) Every multi system operator shall, within sixty days of receipt of request from the broadcaster or its authorised agent or intermediary, provide on non-discriminatory basis, access to its network or convey the reasons for rejection of request if the access is denied to such broadcaster.

Provided that it shall not be mandatory for a multi system operator to carry the channel of a broadcaster if the channel is not in regional language of the region in which the multi system operator is operating or in Hindi or in English language and the broadcaster is not willing to pay the uniform carriage fee published by the multi system operator in its Reference Interconnect Offer.

Provided further that nothing contained in this sub-regulation shall apply in case of a broadcaster who has failed to pay the carriage fee as per the agreement and continues to be in default.

Provided also that imposition of unreasonable terms and conditions for providing access to the cable TV network shall amount to the denial of request for such access.

Provided also that it shall not be mandatory for the multi system operator to carry a channel for a period of next one year from the date of discontinuation of the channel, if the subscription for that particular channel, in the last preceding six months is less than or equal to five per cent. of the subscriber base of that multi system operator taken as an average of subscriber base of the preceding six months.

(11) If a multi system operator before providing access to its network to a broadcaster insist on placement of the channel of such broadcaster in a particular slot or bouquet, such precondition shall amount to imposition of unreasonable terms.

(12) Every multi system operator shall publish in its Reference Interconnect Offer the carriage fee for carrying a channel of a broadcaster for which no request has been made by the multi system operator:

Provided that the carriage fee shall be uniform for all the broadcasters and the same shall not be revised upwards for a minimum period of two years from the date of publication in the Reference Interconnect Offer.

(13) Every multi system operator or his authorised agent who collects on behalf of such multi system operator the carriage fee from a broadcaster shall issue monthly invoice/s to such broadcaster and such invoice/s shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment.

(14) Every multi system operator or their authorized agent shall provide the signals of TV Channels to a local cable operator in accordance with its reference interconnect offer or as may be mutually agreed, within sixty days from the date of receipt of the request and in case the request for providing signals of TV Channels is not agreed to, the reasons for such refusal to provide signals shall be conveyed to the person making a request within sixty days from the date of request.

(15) Every multi system operator or his authorised agent who collects on behalf of such multi system operator the payment from the local cable operator for providing signals shall issue monthly invoice/s to such cable operator and such invoice/s shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment.

(16) Every demand of arrears under these regulations shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain.

CHAPTER - III

REFERENCE INTERCONNECT OFFER

4. General Provisions relating to Reference Interconnection Offer.—(1) Every broadcaster shall, within thirty days of commencement of these regulations, submit to the Authority its Reference Interconnect Offer specifying the technical and commercial terms and conditions including the terms and conditions as mentioned in Schedule II of this regulation and publish it on its website.

Provided that a broadcaster may submit different interconnect offers for different types of digital addressable system.

(2) No broadcaster shall, directly or indirectly, prohibit any digital addressable cable TV system operator from providing its services to any subscriber.

(3) A broadcaster may specify different Reference Interconnect Offers for supply of signals by the multi system operators to different categories of commercial subscribers such as --

- (a) hotels with rating of three stars and above;
 - (b) heritage hotels, as specified in the guidelines for classifications of hotels issued by the Department of Tourism, Govt. of India ;
 - (c) any other hotel, motel, inn and other commercial establishments providing boarding and lodging having fifty or more rooms ; and
- may also specify different reference interconnect offers for programmes telecast on the occasion of special events and viewed on payment basis by fifty persons or more at a place registered under the applicable law for such viewing:

Provided that the Reference Interconnect Offer applicable for ordinary subscriber shall also apply for the commercial subscribers other than those specified in this sub-regulation.

(4) Every broadcaster shall modify their existing Reference Interconnect Offer within thirty days of commencement of these regulations so as to bring them in conformity with provisions of these regulations.

- (5) Any broadcaster, who begins its operation after the commencement of these regulations, shall, thirty days prior to commencement of its operations, submit to the Authority its Reference Interconnect Offer and publish such offer on its website.
- (6) Every broadcaster shall submit to the Authority within seven days any amendment made in its Reference Interconnect Offer and simultaneously publish such amendments on its website in the same manner in which the original Reference Interconnect Offer was published.
- (7) Every multi system operator shall, within thirty days from the date of commencement of these regulations publish its Reference Interconnect Offer specifying the technical and commercial terms and conditions for providing access to its network by the broadcaster and submit a copy to the Authority.
- (8) Every person or firm or company who begins its services as multi system operator shall, before providing its services, publish its Reference Interconnect Offer specifying the technical and commercial terms and conditions for providing access to its network by the broadcaster and submit a copy to the Authority.
- (9) The Authority may, in order to protect the interest of the consumer and the service provider and to promote and ensure orderly growth of broadcasting and cable services, direct the service provider to modify its Reference Interconnect Offer.

CHAPTER - IV

INTERCONNECTION AGREEMENTS

5. General Provisions relating to interconnection agreements.- (1) A multi system operator may enter into an agreement with the broadcaster in accordance with the terms and conditions of the Reference Interconnect Offer published by the broadcaster on such non-discriminatory terms and conditions.

(2) Every broadcaster shall, who publishes revised Reference Interconnect Offer after the commencement of these regulations, give an option to all multi system operators to enter into an agreement in accordance with the revised Reference Interconnect Offer and it shall be open to the multi system operator to enter into fresh agreement or continue with the existing agreement.

(3) Every broadcaster shall, within a period of thirty days from the date of receipt of request from the multi system operator, enter into an interconnection agreement or modify the existing interconnect agreement in accordance with the terms and conditions of the Reference Interconnect Offer published under these regulations or as may be mutually agreed.

(4) Every broadcaster shall offer all its channels to the multi system operator on a-la-carte basis :

Provided that the broadcaster may, in addition to offering all its channels on a-la-carte basis, offer its channels in the form of bouquet.

(5) No broadcaster shall compel any multi system operator to include its channels or bouquet of channels in any package or scheme offered by the multi system operator to its subscribers.

(6) It shall be mandatory for the broadcasters of pay channels to reduce the terms and conditions of the interconnection agreements into writing.

(7) No broadcaster of pay channels shall make available signals of TV channels to any multi system operator without entering into a written interconnection agreement.

(8) Nothing contained in regulations (6) or (7) shall apply to any supply of signals or continuance of supply of signals of TV channels by a broadcaster in pursuance of or in compliance with any order or direction or judgment of any court or tribunal, including any order or direction or judgment of any court or tribunal on any proceeding pending before such court or tribunal.

(9) It shall be the responsibility of every broadcaster of pay channels who enters into an interconnection agreement with a multi system operator to hand over a copy of signed interconnection agreement to such multi system operator and obtain an acknowledgement in this regard within a period of 15 days from the date of execution of the agreement.

(10) In case a broadcaster wants to modify its interconnection agreement entered into with a multi system operator, it shall give a notice of thirty days to the multi system operator and any modification in such agreement may be made as per the terms and conditions of the Reference Interconnect Offer published by the broadcaster under these regulations or as may be mutually agreed.

(11) In case the broadcaster and the multi system operator fail to enter into an interconnection agreement, such broadcaster or multi system operator, without prejudice to the provision of section 14 A of the Act or any other law for time being in force, at any time, may make a request to the Authority to facilitate the process of entering into such agreement and the Authority may issue such directions to the broadcaster and the multi-system operator as it may deem fit.

(12) Nothing contained in sub-regulation (11) shall apply to any matter or issue pending adjudication before any court or tribunal or in respect of which a decree, award or an order has been passed by a court or tribunal.

(13) The interconnection agreement between the multi system operator and its linked local cable operator shall have the details of various services rendered by the local cable operator to the multi system operator and the charges to be paid by the multi system operator to the local cable operator for these services.

(14) The interconnection agreement between the multi system operator and its linked local cable operator shall clearly earmark the responsibility of generation of subscribers' bill by the multi system operator and the roles and responsibilities of the multi system operator and its linked local cable operator on conformance to the quality of service regulations issued by the Authority from time to time.

(15) It shall be open to a multi system operator to decide the packaging of the channels offered to the subscribers from bouquet of channels provided to it by the broadcaster :

Provided that in case the multi system operator does not offer to a subscriber the entire bouquet of channels provided to it by the broadcaster but only certain channels of such bouquet or packages the channels of such bouquet in a manner resulting in different subscriber base for different channels of such bouquet, the payment to the broadcaster for such bouquet shall be calculated on the basis of the subscriber base for that channel of the bouquet which has highest subscriber base.

(16) Every service provider shall enter into a new agreement before the expiry of the existing agreement and in case the service provider fails to enter into the new agreement before the expiry of the said agreement, the provisions of the existing agreement shall continue to apply till the new agreement is entered into between the service providers or for the next three months from the date of expiry of existing agreement, whichever is earlier and if the service providers are able to enter into an agreement before the expiry of the said three months, the new agreement shall apply from the date of expiry of earlier agreement:

Provided that if service providers are not able to enter into a new agreement, they may be entitled to disconnect the signals of TV Channels by giving three weeks notice published in two local newspapers, out of which one shall be published in the newspaper of the regional language of the area for which the said agreement is applicable.

(17) It shall be mandatory for the multi system operator to reduce the terms and conditions of the interconnection agreements into writing.

(18) No multi system operator, shall make available signals of TV channels to any linked local cable operator without entering into a written interconnection agreement.

(19) Nothing contained in regulations (17) or (18) shall apply to any supply of signals or continuance of supply of signals of TV channels by a multi system operator in pursuance of or in compliance with any order or direction or judgment of any court or tribunal, including any order or direction or judgment of any court or tribunal on any proceeding pending before such court or tribunal.

(20) It shall be the responsibility of every multi system operator to hand over a copy of signed interconnection agreement who enters into an interconnection agreement with a linked local cable operator/s to hand over a copy of signed interconnection agreement to such cable operator and obtain an acknowledgement in this regard within a period of 15 days from the date of execution of the agreement.

(21) No service provider shall demand from any other service provider a minimum guaranteed amount as subscription fee for the channels provided by such service provider.

CHAPTER - V

DISCONNECTION OF SIGNALS OF TV CHANNELS

6. Disconnection of signals of TV Channel .- (1) No broadcaster shall disconnect the signals of a TV Channels of a multi system operator without giving three weeks notice to such multi system operator, clearly specifying the reasons for the proposed disconnection.

(2) No multi system operator shall disconnect the signals of a TV Channels of a linked local cable operator, without giving three weeks notice to such local cable operator, clearly specifying the reasons for the proposed disconnection.

(3) No multi system operator shall disconnect the re-transmission of any TV channel without giving three weeks notice to the broadcaster, clearly specifying the reasons for the proposed disconnection.

(4) No local cable operator shall disconnect the re-transmission of any TV channel without giving three weeks notice to the multi system operator, clearly specifying the reasons for the proposed disconnection.

(5) Every notice of disconnection of signals of TV channel under sub-regulation (1), (2), (3) and (4) and every notice of disconnection of re-transmission of TV channel under sub-regulation (2), (3) and (4) shall be published in two leading local newspapers of the State in which the service provider is providing the services, out of which one notice shall be published in the newspaper in local language.

(6) The period of three weeks specified under sub-regulation (1), (2), (3) and sub-regulation (4) shall start from the date of publication of the notice in newspapers or the date of service of the notice on service provider, whichever is later and in case the notices are published in newspaper on different dates, the period of three weeks shall be counted from the later of the two dates.

CHAPTER - VI

MISCELLANEOUS

7. Conversion of free to air channel into pay channel or a pay channel into free to air channel.- A channel once declared free to air channel or pay channel shall remain such channel for at least a period of one year and any broadcaster shall, before converting a free to air channel into pay channel or a pay channel into free to air channel, inform the Authority and shall give one month's notice before such conversion in two local newspapers, out of which one shall be published in the newspaper of the regional language of the area in which such conversion takes place.

8. Intervention by the Authority .- The Authority may, in order to protect the interest of the consumer or service provider or to promote and ensure orderly growth of the broadcasting and cable sector or for monitoring and ensuring compliance of these regulations, by order or direction, intervene, from time to time.

9. Reporting Requirements.- (1) Every multi system operator shall submit to the Authority information, in the proforma specified in Schedule-III to these regulations, all interconnect agreements entered into by it with the broadcaster and local cable operator and subsequent modifications made therein.

(2) Every existing multi system operator shall submit to the Authority by 31st July, 2012, all interconnect agreements entered into by it and amendments made therein prior to the date of notification of these regulations.

(3) Every multi system operator commencing its services after the notifications of these regulations shall submit to Authority its interconnection agreement within thirty days of entering into the agreement or 31st July, 2012 whichever is later.

(4) Every broadcaster shall furnish the details of carriage fee paid by him to the multi system operator along with the information furnished by him under the Register of Interconnect Agreements (Broadcasting and Cable Services) Regulation 2004 (15 of 2004), as amended from time to time. Such information henceforth shall also include details of carriage fee paid to the multi system operator by the broadcaster.

WASI AHMAD, Advisor (B & CS)

[ADVT. III/4/Exty./142/12]

Note : -----The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulation, 2012.

Schedule I**Digital Addressable cable TV Systems Requirements****A) Conditional Access System (CAS) & Subscriber Management System (SMS) :**

1. The current version of the conditional access system should not have any history of the hacking.
2. The fingerprinting should not get invalidated by use of any device or software.
3. The STB & VC should be paired from head-end to ensure security.
4. The SMS and CA should be integrated for activation and deactivation process from SMS to be simultaneously done through both the systems. Further, the CA system should be independently capable of generating log of all activation and deactivations.
5. The CA company should be known to have capability of upgrading the CA in case of a known incidence of the hacking.
6. The SMS & CAS should be capable of individually addressing subscribers, on a channel by channel and STB by STB basis.
7. The SMS should be computerized and capable to record the vital information and data concerning the subscribers such as:
 - a. Unique Customer Id
 - b. Subscription Contract number
 - c. Name of the subscriber
 - d. Billing Address
 - e. Installation Address
 - f. Landline telephone number
 - g. Mobile telephone number
 - h. Email id
 - i. Service/Package subscribed to
 - j. Unique STB Number
 - k. Unique VC Number
8. The SMS should be able to undertake the:
 - a. Viewing and printing historical data in terms of the activations, deactivations etc
 - b. Location of each and every set top box VC unit
 - c. The SMS should be capable of giving the reporting at any desired time about:

- i. The total no subscribers authorized
 - ii. The total no of subscribers on the network
 - iii. The total no of subscribers subscribing to a particular service at any particular date.
 - iv. The details of channels opted by subscriber on a-la carte basis.
 - v. The package wise details of the channels in the package.
 - vi. The package wise subscriber numbers.
 - vii. The ageing of the subscriber on the particular channel or package
 - viii. The history of all the above mentioned data for the period of the last 2 years
9. The SMS and CAS should be able to handle at least one million subscribers on the system.
 10. Both CA & SMS systems should be of reputed organization and should have been currently in use by other pay television services that have an aggregate of at least one million subscribers in the global pay TV market.
 11. The CAS system provider should be able to provide monthly log of the activations on a particular channel or on the particular package.
 12. The SMS should be able to generate itemized billing such as content cost, rental of the equipments, taxes etc.
 13. The CA & SMS system suppliers should have the technical capability in India to be able to maintain the system on 24x7 basis throughout the year.
 14. CAS & SMS should have provision to tag and blacklist VC numbers and STB numbers that have been involved in piracy in the past to ensure that the VC or the STB can not be re-deployed.

(B) Fingerprinting:

1. The finger printing should not be removable by pressing any key on the remote.
2. The Finger printing should be on the top most layer of the video.
3. The Finger printing should be such that it can identify the unique STB number or the unique Viewing Card (VC) number.
4. The Finger printing should appear on all the screens of the STB, such as Menu, EPG etc.
5. The location of the Finger printing should be changeable from the Headend and should be random on the viewing device.
6. The Finger printing should be able to give the numbers of characters as to identify the unique STB and/or the VC.

7. The Finger printing should be possible on global as well as on the individual STB basis.
8. The Overt finger printing and On screen display (OSD) messages of the respective broadcasters should be displayed by the MSO/LCO without any alteration with regard to the time, location, duration and frequency.
9. No common interface Customer Premises Equipment (CPE) to be used.
10. The STB should have a provision that OSD is never disabled.

(C) Set Top Box (STB) :

1. All the STBs should have embedded Conditional Access.
2. The STB should be capable of decrypting the Conditional Access inserted by the Headend.
3. The STB should be capable of doing Finger printing. The STB should support both Entitlement Control Message (ECM) & Entitlement Management Message (EMM) based fingerprinting.
4. The STB should be individually addressable from the Headend.
5. The STB should be able to take the messaging from the Headend.
6. The messaging character length should be minimal 120 characters.
7. There should be provision for the global messaging, group messaging and the individual STB messaging.
8. The STB should have forced messaging capability.
9. The STB must be BIS compliant.
10. There should be a system in place to secure content between decryption & decompression within the STB.
11. The STBs should be addressable over the air to facilitate Over The Air (OTA) software upgrade.

Schedule II

Terms and conditions which should compulsorily form part of Reference Interconnect Offers for interconnection between broadcaster and multi system operator for the Digital Addressable Cable TV System platforms.

Licence Fee	<p>For each month or part thereof during the Term of the agreement, the multi system operator shall pay to _____ (name of the Broadcaster) the Monthly Licence Fee which shall be the Rate multiplied by the Monthly Average Subscriber Level.</p> <p>The a-la-carte and bouquet "Rate" per Subscriber is set out in Annexure to this RIO. The rates mentioned in the Annexure to this RIO, as referred to above, are exclusive of all taxes and levies.</p> <p>The "Monthly Average Subscriber Level" is equal to the sum of the number of subscribers on the first and last day of the month in question divided by two.</p> <p>For the purpose of calculation of the Monthly License Fee payable to _____ (name of the Broadcaster), "Subscriber" means, for any calendar month, each Set Top Box, which is availing the Channel(s) of _____ (name of the Broadcaster) through the multi system operator.</p> <p>Calculation of License Fee:</p> <p>I. In case a multi system operator avails one or more Bouquet(s) of _____ (name of the Broadcaster):</p> <p>(a) If the multi system operator is providing the Bouquet(s) as a whole to its subscribers, the Monthly License Fee for such Bouquet(s) shall be equal to the Bouquet rate as set out in the Anenxure multiplied by the number of monthly average number of subscribers availing the Bouquet(s).</p>
-------------	--

(b) if the multi system operator does not offer such opted bouquet(s) as a whole to its subscriber but offers only certain channels comprised in such bouquet or packages the channels comprised in such opted bouquet in a manner resulting in different subscriber base for different channels comprised in such opted bouquet, then the payment to _____ (name of the Broadcaster) for such entire opted bouquet by the multi system operator, shall be calculated on the basis of subscriber base for the channel which has highest subscriber base amongst the channels comprised in the bouquet.

II In case a multi system operator avails one or more or all channels of _____ (name of the Broadcaster) on ala carte rate basis:

(a) If the multi system operator is providing the channels on ala carte basis to its subscribers, the Monthly License Fee for such ala carte channels shall be equal to the ala carte rate as set out in the Annexure multiplied by the number of monthly average number of subscribers availing the channels on ala carte basis.

(b) if the multi system operator does not offer such opted ala carte channel(s) as ala carte to its subscriber but offers the ala carte channel (s) in packages, then the payment to _____ (name of the Broadcaster) for each of the ala carte channels, shall be calculated on the basis of subscriber base of the package in which such opted ala carte channel has been placed.

III In case a multi system operator avails one or more channels on ala carte rate basis and also opts for different Bouquet(s) not comprising of channels opted on ala carte basis of _____ (name of the Broadcaster):

(a) For bouquet(s), the monthly license fee shall be calculated on the basis of sub clause I above.

(b) For ala carte channels, the monthly license fee shall be calculated on the basis of sub clause II above.

Payment of the License Fee shall be subject to deduction of any withholding tax/ TDS in accordance with the provisions of the Indian Income Tax Act,

	1961, as amended from time to time.
Payment Terms	<p>The Monthly Licence Fee shall be paid monthly in arrears within fifteen (15) days of receipt of invoice raised on the basis of report of the multi system operator by _____ (name of the Broadcaster) without any deduction except deduction of withholding tax/TDS as provided in this RIO.</p> <p>Within seven days of end of each month, the multi system operator shall provide opening, closing and average number of subscribers for that month, based on which _____ (name of the Broadcaster) shall raise an invoice on the multi system operator. In case the multi system operator fails to send the report within the said period of seven days, _____ (name of the Broadcaster) shall have the right to raise a provisional invoice and the multi system operator shall be under obligation to pay the license fee on the basis of such provisional invoice in accordance with the terms of this clause. However the provisional invoice shall be for an amount not more than the monthly license fee payable by the multi system operator for the immediately preceding month. On receipt of the report from the multi system operator, the parties would conduct reconciliation between the provisional invoice raised by _____ (name of the Broadcaster) and the report sent by the multi system operator.</p> <p>The multi system operator shall be required to make payments by the Due Date in accordance with the terms hereof, and any failure to do so on the part of the multi system operator shall constitute a material breach hereunder. Late payments shall also attract interest calculated from the date payment was due until the date payment is made in full at a pro rata monthly rate of ____%. The imposition and collection of interest on late payments does not constitute a waiver of the multi system operator's obligation to pay the License Fee by the Due Date, and _____ (name of the Broadcaster) shall retain all of its other rights and remedies under the Agreement.</p> <p>All Licence Fee payments hereunder are exclusive of all applicable indirect taxes including all and any service taxes, VAT, works contract taxes, customs duties, excise duties, entertainment taxes and other such taxes. All such taxes</p>

	<p>shall be at multi system operator's cost and will be charged at the prevailing rates by _____ (name of the Broadcaster) to the multi system operator.</p> <p>If payment of the Licence Fee is subject to deduction of any withholding tax/TDS in accordance with the provisions of the Indian Income Tax Act 1961, as amended, the multi system operator shall provide tax withholding certificates to _____ (name of the Broadcaster) within such period as has been specified in the Income Tax Act/ Rules/ Notifications/ Circulars issued thereunder.</p>
Delivery and Security	<p>All _____ (name of the Broadcaster) Channels must be delivered by multi system operator to subscribers in a securely encrypted manner and without any alteration.</p> <p>The transmission specifications and infrastructure allocated by multi system operator in respect of the broadcast signal of the _____'s (name of the Broadcaster) Channels by multi system operator to its subscribers shall be no worse than that of the cable signal of any other channel within the same genre on its digital addressable cable TV system platform.</p>
Anti-Piracy	<p>In order to prevent theft, piracy, unauthorized retransmissions, redistribution or exhibition, copying or duplication of any Channel, in whole or in part, (hereinafter collectively referred to as "Piracy"), the multi system operator shall, prior to the commencement of the Term of the agreement and at all times during such Term, employ, maintain, and enforce fully effective conditional access delivery and content protection and security systems, and related physical security and operational procedures (hereinafter collectively referred to as the "Security Systems") as may be specified (security specifications), in a non-discriminatory manner in writing, from time to time, by the _____ (name of the Broadcaster).</p> <p>To ensure the multi system operator's ongoing compliance with the security requirements set out in the Agreement, _____ (name of the Broadcaster) may require technical audits ("Technical Audit(s)") conducted by an independent security technology auditor ("Technical Auditor"), approved by _____ (name of the Broadcaster) in writing no more than twice per year</p>

during the Term, at _____ (name of the Broadcaster)'s cost and expense. If the results of any Technical Audit are not found to be satisfactory by either the multi system operator or _____ (name of the Broadcaster), then _____ (name of the Broadcaster) shall work with the multi system operator in resolving this issue in the next fourteen (14) business days. If a solution is not reached at by then, _____ (name of Broadcaster) may, in its sole discretion, suspend the multi system operator's right to distribute the Channels or take other actions as provided under the Agreement, until such systems, procedures and security measures have been corrected to _____ (name of the Broadcaster)'s satisfaction multi system operator shall bear the cost and expense of any subsequent Technical Audit to verify that the systems, procedures and security measures have been corrected by the multi system operator to _____ (name of the Broadcaster)'s satisfaction.

Multi system operator shall deploy finger printing mechanisms to detect any piracy, violation of copyright and unauthorized viewing of the Channels, distributed / transmitted through its Platform at least every 10 minutes on 24 x 7 x 365(6) basis.

Multi system operator shall not authorize, cause or suffer any portion of any of the Channels to be recorded, duplicated, cablecast, exhibited or otherwise used for any purpose other than for distribution by multi system operator at the time the Channels are made available. If multi system operator becomes aware that any unauthorized third party is recording, duplicating, cable casting, exhibiting or otherwise using any or all of the Channels for any other purpose, multi system operator shall within ten minutes of so becoming aware of such recording, duplicating, cable casting, exhibiting or otherwise using any or all of the Channels for any other purpose, notify _____ (name of the Broadcaster) and the multi system operator shall also switch off the concerned Set Top Box to prevent such unauthorized use. However, use of a Set Top Box with Personal Video Recorder/ Digital Video Recorder facility which has been supplied by the multi system operator shall not be treated as unauthorized use, as long as such Set Top Box is used in accordance with the terms and conditions of the subscription agreement between the multi system

	<p>operator and the subscriber.</p> <p>If so instructed by Information (as defined below) by _____ (name of the Broadcaster), the multi system operator shall shut off or de-authorize the transmission to any unauthorized subscriber/ subscriber indulging in piracy, within ten minutes from the time it receives such instruction from _____ (name of the Broadcaster). Any communication under this clause shall be considered as valid Information only if (i) the information is sent through e mail in a format as mutually agreed by the parties and (ii) the information is sent by a person(s) who is designated to send such information. However the "information" may even be provided by _____ (name of the Broadcaster) representatives through other means of communications such as telephonic message, fax etc and the said "information" shall later be confirmed by _____ (name of the Broadcaster) through e mail and the multi system operator shall be under obligation to act upon such information.</p>
Reports	<p>Multi system operator will maintain at its own expense a subscriber management system ("SMS") which should be fully integrated with the CAS (Conditional Access System).</p> <p>Multi system operator shall provide to _____ (name of the Broadcaster) complete and accurate opening and closing subscriber monthly reports for the _____ (name of the Broadcaster) Channels and the tier and/or package containing the _____ (name of the Broadcaster) Channels within seven (7) days from the end of each month in the format provided by _____ (name of the Broadcaster).</p> <p>Such reports shall specify all information required to calculate the Monthly Average Subscriber Level (including but not limited to the number of Subscribers for each _____ (name of the Broadcaster) Channel and each package in which a _____ (name of the Broadcaster) Channel is included) and the Licence Fees payable to _____ (name of the Broadcaster) and shall be signed and attested by an officer of the multi system operator of a rank not less than Head of Department/Chief Financial Officer who shall certify that all information in the Report is true and correct.</p>

Audit

_____ (name of the Broadcaster)'s representatives shall have the right, not more than twice in a calendar year, to review and / or audit the subscriber management system, conditional access system, other related systems and records of Subscriber Management System of the multi system operator relating to the Channel(s) provided by the broadcaster for the purpose of verifying the amounts properly payable to _____ (name of the Broadcaster) under the Agreement, the information contained in Subscriber Reports and full compliance with the terms and conditions of the Agreement. If such review and or audit reveals that additional fees are payable to _____ (name of the Broadcaster), the multi system operator shall immediately pay such fees, as increased by the -----

Late Payment Interest Rate. If any fees due for any period exceed the fees reported by the multi system operator to be due for such period by two (2) percent or more, multi system operator shall pay all of _____ (name of the Broadcaster)'s costs incurred in connection with such review and / or audit, and take any necessary actions to avoid such errors in the future.

The multi system operator shall remain the sole owner and holder of all customer databases compiled by the multi system operator under the Agreement.

Multi system operator will maintain at its own expense a subscriber management system ("SMS") capable of, at a minimum:

- (i) maintaining a computerised customer database capable of recording adequate details of each Subscriber, including name, address, chosen method of payment and billing;
- (ii) administering subscriptions of Subscribers by producing and distributing contracts for new Subscribers and setting up and maintaining an infrastructure whereby Subscriber contracts are collected and recorded in the SMS database for ongoing administration;
- (iii) handling all ongoing administrative functions in relation to Subscribers, including, without limitation, billing and collection of subscription payments,

	<p>credit control, sales enquiries and handling of complaints;</p> <p>(iv) administering payments of any commission fees from time to time payable to the multi system operator's authorised agents for the sale to Subscribers of programming packages;</p> <p>(v) obtaining and distributing receivers and smartcards, if applicable, to Subscribers, and issue replacement smartcards from time to time in its discretion; and</p> <p>(vi) enable new Subscribers via the SMS over-the-air addressing system and disable defaulting Subscribers from time to time in its discretion.</p>
Term	<p>As mutually agreed between _____ (name of the Broadcaster) and the multi system operator subject to a minimum of One (1) Year from the date of signing of the Agreement unless terminated earlier in accordance with the Agreement.</p> <p>The Term of the Agreement may be extended on terms and conditions to be mutually agreed and recorded in writing between the parties.</p>
Termination	<p>Either Party has a right to terminate this Agreement by a written notice, subject to applicable Law, to the other in the event of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. material breach of this Agreement by the other Party which has not been cured within thirty (30) days of being required in writing to do so; 2. the bankruptcy, insolvency or appointment of receiver over the assets of the other Party; 3. The digital addressable cable TV system licence or any other material licence necessary for multi system operator to operate its digital addressable cable TV system service being revoked at anytime other than due to the fault of multi system operator. <p>_____ (name of the Broadcaster) shall have the right to terminate this Agreement by a written notice to multi system operator if (i) multi system operator breaches any of the Anti Piracy Requirements and fails to cure such</p>

	<p>breach within ten (10) days of being required in writing to do so; or</p> <p>(ii) _____ (name of the Broadcaster) discontinues the _____ (name of the Broadcaster) Channels with respect to all distributors in the Territory and provides multi system operator with at least ninety (90) days prior written notice.</p> <p>Multi system operator shall have the right to terminate this Agreement on written notice to _____ (name of the Broadcaster) if multi system operator discontinues its digital addressable cable TV system business and provides at least ninety (90) days prior written notice.</p>
Jurisdiction	<p>The Governing Law shall be the Indian Law and TDSAT, shall have exclusive jurisdiction in respect of any dispute between the parties, arising out of /in connection with or as a result of the Agreement.</p>

[illegible]

(B) BOUQUET RATES**BOUQUET - 1**

Channels	Rate to multi system operator (Rs)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

BOUQUET 3

Channels	Rate to multi system operator (Rs)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

BOUQUET- 2

Channels	Rate to multi system operator (Rs)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Schedule — III

**Performa for reporting by Multi System Operator of interconnect agreements entered into by them with
Broadcasters & Local Cable Operators**

Column →	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S. No	Name of contracting parties	Complete Address of party with District, State, Pin Code and telephone number	Service Area of Operation	Name of the Bouquet with Number of channels	Rate of bouquet	Subscriber Base (Month wise w.e.f. July of the previous year and upto June of the current year)	Name of a-la-carte Channel & Number of channels	Rate of a-la-carte channel

Column →	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Discount, if any	Subscriber Base (Month wise w.e.f. July of the previous year and upto June of the current year)	IRD/VC No. - Channel Wise	Term of IRD	Agreement Number with date	Date of Commence-ment of the agreement	Date of expiry of the agreement	Carriage fee paid by the broadcaster	Remarks, if any

Annexure

Explanatory Memorandum**I. Background**

1. On 10.12.2004, TRAI made an interconnection regulation applicable for broadcasting and cable TV sector. The regulation was called the "Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 (13 of 2004)". There have been six amendments made to this regulation.
2. The interconnection regulations provide for the basic structure on the matters of interconnection. These regulations cover arrangements among service providers for interconnection and revenue share, for all broadcasting and cable services. The main features of the regulations are: provision of 'must provide' (i.e. non discriminatory access) for the broadcasters and the provision for 'disconnection of TV signals'. The regulations prescribe notice period for disconnection. In the notice for disconnection, the reasons for disconnection are to be given. No notice for disconnection is required if there is no written agreement permitting distribution of signals. For the information of the consumers, it has been provided that the notice for disconnection should be published in newspapers in accordance with the relevant provisions of the regulations. These regulations also provide for publishing of Reference Interconnect Offer by broadcasters for non-addressable as well as addressable cable TV systems.
3. In the last few years, the exponential growth in the number of TV channels (both Free To Air and Pay) combined with the inherent limitations of the analogue cable TV systems, has posed several challenges in the cable TV sector, mainly due to capacity constraints and non-addressable nature of the network. With time and evolution of technology, new addressable digital TV platforms like DTH, IPTV etc. were introduced to the masses. The evolution of technology also paved way for bringing about digitization with addressability in the cable TV sector. Accordingly, after studying the subject at length and undertaking a public consultation process, the Authority, on 5th August 2010, gave its recommendations on implementation of Digital Addressable Cable TV Systems (DAS) across the country along with a roadmap to achieve the same.

4. The Government, on 25th October, 2011, issued an Ordinance amending the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, paving way for the implementation of digital addressable cable TV systems in India. Thereafter, the Government also issued a notification dated 11th November, 2011, which laid down the roadmap for implementation, in a four phased manner, from June 2012 to December, 2014. The Ordinance dated 25th October, 2011, subsequently, in December, 2011, became an Act.

5. Considering the amended provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, and the notification dated 11.11.2011 mentioned above, the Authority initiated a consultation process on the issues relating to implementation of digital addressable cable TV systems. In this connection a consultation paper titled "Issues related to Implementation of Digital Addressable Cable TV Systems" was issued on 22.12.2011. The issues for consultation related to the amendments to the existing interconnection regulations, the subscription revenue share between the MSO and LCO, whether "must carry" provision should be mandated for the MSOs, whether the carriage fee is to be regulated and whether there should be a specified standard interconnection agreement between service providers applicable for DAS areas. An Open House Discussion (OHD) was also held in New Delhi on 13th March, 2012.

II. Analysis of issues

6. The following is a summary of main issues, comments of the stakeholders and analysis thereon.

Note: To make it convenient for ease of reference and understanding by all the stakeholders, the instant regulations consolidate all the earlier interconnection regulations and the regulations now made are applicable for digital addressable cable TV systems.

A. Suggested Amendments to Interconnection Regulations

The issue for consideration was whether any of the existing clauses of the Interconnection Regulations require modifications.

7. During the course of the consultation process, broadcasters/aggregators suggested modifications in certain clauses of the existing interconnection regulations such as reduction in notice period for disconnection of signals, procedure for auditing of the Subscriber Management System (SMS) of the service provider and on the technical side it was suggested that a provision be made in the interconnection regulations for integration of SMS and the Conditional Access System (CAS) so as to ensure complete addressability of the system. It was also suggested that the provisions may be made in the regulations for anti piracy and fingerprinting measures and for making provision for filing of interconnect agreements by MSOs/LCOs and also a provision for minimum period of subscription. It was also suggested that clause 3.2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004, relating to "must provide" may also be qualified by making it inoperative in cases of service providers who have failed to comply with any of the regulations. It was also suggested by the stakeholders that certain definitions in the existing interconnection regulation may be required to be amended to bring them in line with the provisions of Cable Television Act as amended in 2011. Some MSOs expressed the view that they are not in favor of any modification in existing clauses. Some of the LCOs have suggested that there is a need to amend the clauses of interconnection regulations relating to the notice period for disconnection and for making provisions for revenue sharing arrangements.

8. On the issue of filing of interconnect agreements by the MSOs, the Authority considered the suggestion and decided to incorporate a provision in this regard in this regulation so as to bring in the transparency in the system. A provision has been made in this regulation for reporting the details of interconnect agreements by the MSOs along with the details of carriage fee paid by the broadcasters. The reporting requirement, prescribed in the present regulations, makes a provision for the broadcasters to file the details of carriage fee paid by them. On the issue of amendments to definitions, the definitions such as "addressable system", "broadcaster", "cable operator", "multi system operator", "pay channel" and "subscriber management system" have been aligned with that of the amended Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and also the amended Cable Television Networks Rules, 1994. On the issue of minimum period of subscription, a provision has been made in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Digital Addressable Cable TV Areas) Tariff Order, 2012. On the issue of Notice period for disconnection, the Authority considered the fact that the notice period should be sufficient for the affected

parties to be able to approach the appropriate forum to plead for intervention and to give the consumers an opportunity to approach the necessary forum. The Authority, therefore, decided that the existing period of the notice of 21 days is to be retained. On the suggestion of the audit of SMS, the Authority considered the fact that the existing provisions of the interconnect regulations provide for upto two audits in a calendar year. The Authority felt that this is sufficient opportunity for audit and, therefore, decided that there is no need to modify the existing provisions in this regard. On the issue of integration of SMS and CAS, the Authority observed that the existing interconnection framework provides for integration of SMS and CA system for activation and deactivation process from SMS to be simultaneously done through both the systems. The Authority is of the view that this provision is adequate and therefore no change is required. On the issue of Anti Piracy and fingerprinting the Authority observed that the existing framework provides that operator shall deploy finger printing mechanisms to detect any piracy, violation of copyright and unauthorized viewing of the Channels, distributed / transmitted through its platform. The Authority is of the view that this provision is adequate and therefore no change is required on this issue. On the issue of Qualified "Must Provide", the Authority observed that the violations of regulations are to be dealt with as per the provisions of the TRAI Act, 1997. The Authority is, therefore, of the view that no further qualifications are required in this provision.

B. The "Must Carry" provision

9. The issue is that should the 'must carry' provision be mandated for the MSO. If so, what should be the qualifying conditions and the manner in which an MSO should offer access to its network for the carriage of TV channel. The majority of the broadcasters are in favour of mandating must carry provisions to balance out the 'must provide' clause prescribed in the existing interconnect regulations. They have suggested that the manner of offering network access should be on a non-discriminatory basis and the qualifying conditions may include openness to audit & transparency, non-discriminatory listing of channels and all channels should feature genre-wise in the EPG of MSO. One broadcaster has also suggested that the 'must carry' provisions need not be mandated.

10. Majority of the MSOs and LCOs have suggested that there should not be any must carry provision. Some of them have suggested that it can be mandated only for DD channels. Regarding the manner, one LCO has suggested that Carriage fee should be the qualifying

condition for all 'must carry' channels except Doordarshan channels. Few LCOs have supported the must carry provision and stated that it should be regulated by TRAI. Other stakeholders who have offered their comments are not in favour of 'must carry' provision.

11. In the digital transmission environment, the capacity to carry the channels is very high. So one of the main advantages of a digital environment to the subscriber is the availability of large number of channels. However, there is a component of cost to carry channels. If the operator is compensated for the cost of carriage of a channel, there should not be any technological or other infrastructural constraints for the operator to carry a channel. Further, as per the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2012, the channel carrying capacity of the multi system operator is to be specified by the Authority.
12. The analysis of the operational channels (Annexure-A attached with this Explanatory Memorandum) shows that the maximum number of channels that are relevant to a State or Union Territory, language-wise, are 473 (in Andhra Pradesh) out of the 650 operational private channels (as on April, 2012). Besides this there are 18 channels of the Prasar Bharati and one Lok Sabha channel (in total 19 channels) that may also be relevant for all the States and the UTs to cater to the infotainment requirements of minority populace of these States and UTs. It is also noted that the Ministry of Information and Broadcasting has granted permission to 831 channels under uplinking/downlinking guidelines, as on 6th March, 2012. It is also likely that certain more channels may get operational by 1.1.2013. Thus, it is logical that maximum number of channels that may be required to be carried in a digital addressable cable TV system network, for present, is taken as 500 channels per headend. Therefore, the present regulations provide for creating a capacity of 500 channels per headend by 1.1.2013. Further, it has been seen that there are two types of MSOs viz., large sized MSOs having subscriber base of more than 25,000 subscribers with upper limit running into lakhs of subscribers and smaller MSOs having around 25,000 subscribers or lesser number of subscribers. Due to the larger size of operations, the large sized MSOs are better equipped to have the capacity to set up digital addressable cable TV systems in lesser time than the smaller sized MSOs. Therefore, to provide more time to smaller MSOs to create capacity of 500 channels per head end, the time line has been prescribed as 1st April, 2013 and for the large sized MSOs, the time line has been kept as 1st January, 2013. However, considering the fact that the four metros of Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai are to go digital on 1st July, 2012, and many of the MSOs may not be able to create a capacity

to carry a minimum 500 channels per headend by this date, in the first instant, they have been allowed to operate with a minimum capacity of 200 channels per headend.

13. To allow the multi system operator to provide the access to its cable network smoothly, a time frame of sixty (60) days has been provided for in the regulations which is equivalent to the time frame given to the broadcaster under the must provide provisions. In no case this time period be more than sixty days (60 days) from the date of request seeking access to the network of the multi system operator.

14. A responsibility has also been cast upon the broadcaster or the access seeker to the cable network of the MSO under the provisions of 'must carry' to ensure the subscription of the channel at a minimum level of more than or equal to five per cent. (5%) of the subscriber base of that MSO taken on an average of subscriber base for the preceding six months. In case of failure to maintain this subscriber base, the network provider, in his discretion, can refuse to grant further access to the network for a period of next one year. Such a refusal would not be considered a violation of the "Must carry" provision.

C. "Carriage fee"

15. The issues are should the carriage fee be regulated and if so, should its quantum be linked to some parameters. News Broadcaster Association is of the view that carriage fee should be regulated. This Association is of the view that if must carry is mandated, the question of carriage fee does not arise. Majority of the broadcasters and one association of broadcasters are not in favor of regulating the carriage fee and have suggested that it should be based on the mutual negotiation between the broadcaster and MSO. Few who favored suggested that the parameters can be the subscriber base of the MSO, number of STB installed etc. One of the broadcaster suggested that carriage fee should not exceed 10% of the subscription fee collected for the channels not covered under the must carry mandatory clause.

16. MSOs are not in favor of any kind of regulatory intervention on carriage fee. Most of the LCOs are not in favor of regulating the carriage fee. Some of the LCOs suggested that the carriage fee should be regulated and can be linked with the no. of STBs installed, gross collection of subscription amount, size and locality of the network etc. Some LCOs are suggesting that LCO should also get a part from the carriage fee.

17. In the addressable systems, due to transparency in ascertaining the number of subscribers, the subscription revenue is expected to go up. Therefore, the dependence of MSOs on the carriage fee, as a source of revenue, is likely to be reduced. Considering all the aspects, the Authority is of the view that there is a need to regulate the carriage fee. Accordingly, the following scheme has been worked out. The MSOs who charge carriage fee are required to declare the carriage fee for carrying a TV channel. The carriage fee shall be charged in a non-discriminatory and transparent manner. Also the carriage fee can not be revised upward for a minimum period of 2 years. The details of the carriage fee is to be filed with the Authority. In case the Authority finds it necessary, it shall intervene and ask for appropriate modifications in the carriage fee.

D. Standard Interconnect Agreement (SIA)

18. The issue is whether TRAI prescribe a standard interconnection agreement between service providers. Nearly half of the broadcasters who offered their comments on the issue are not in favour of prescribing SIA by the Authority whereas others are in favour of SIA prescription by the Authority. Those who favoured, suggested that the piracy and termination clauses should be reviewed.

19. MSOs are in favour of SIA prescription by the Authority except for one MSO who has suggested that RIO based mechanism, has worked well for DTH sector, so it should be extended to DAS. Majority of LCOs are in favour of SIA whereas some of them have suggested that there is no immediate requirement of SIA.

20. The Authority is of the view that as the interconnection regulations already provide for the necessary regulatory framework for addressable systems, in the form of RIO, which were not there in the year 2006 when SIA was prescribed for CAS, there is no need for prescribing Standard Interconnect Agreement between Broadcaster and MSO and also between MSO and LCO in the Digital Addressable Cable TV System. The Authority is of the view that the RIO based prescription should prevail in DAS also.

E. Advertisement free (ad-free) channels

21. The issues are what should be the provisions in the interconnection regulations in respect of advertisement free channels and what should be the revenue sharing arrangement between the broadcasters and distributors in respect of such channels. Some broadcasters and an MSO

stated that existing requirements/stipulations of Interconnect Regulations, viz. 'must provide' should not apply to advertisement free channels and the broadcasters & respective service providers should be free to enter into agreements on mutually acceptable terms in order to provide incentives to all the players in the value chain to create, develop and market new innovative and non-mass-market advertisement based television content. Majority of other stakeholders, who have responded to these issues, say that the provisions of the existing interconnection regulations should be applicable to advertisement free channels also so that consumers are not deprived of such channels. Some cable operators are of the view that provisions of the interconnection regulations as applicable to the notified CAS areas should be applied for the advertisement free channels. As far as the sharing of the subscription revenue of the ad-free channels is concerned, all the broadcasters have expressed the views that it should be left for the commercial negotiations between the service providers. Some of the other stakeholders have suggested that revenue share be decided in the same way as any other pay channel while others have suggested different percentages for broadcaster, MSO and LCO, however, without any justification for this suggestion.

22. The issue of rates of advertisement free channels and sharing of subscription revenues of such channels has been dealt with by separately in the provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (First Amendment) Order, 2012. Authority is of the view that there is no need to change the existing policy of leaving it to the market forces. To prevent denial of the signals of the channels by the broadcaster to the MSO or denial by the MSO to carry the channels, such channels can not be mandated to be outside of the purview of the clauses on 'must provide' and 'must carry' of the interconnection regulations as this would not be in the interests of the consumers.

Annexure-A

State-wise/UT-wise maximum number of TV channels language-wise relevant to the particular state or UT out of operational 650 private channels granted permission by the Ministry of Information and Broadcasting under the downlinking guidelines (data as on April, 2012)

Sl. No.	States	Number of channels	Languages
1	Andhra Pradesh	473	Hindi/ English/Telgu+19 channels*
2	Arunachal Pradesh	425	Hindi/ English/NE and Assamese+19 channels
3	Assam	425	Hindi/ English/NE and Assamese+19 channels
4	Bihar	428	Hindi/ English/Bhojpuri+19 channels
5	Chhattisgarh	420	Hindi/ English+19 channels
6	Goa	438	Hindi/ English/Marathi+19 channels
7	Gujarat	428	Hindi/ English/Gujrati+19 channels
8	Haryana	441	Hindi/ English/Punjabi+19 channels
9	Himachal Pradesh	441	Hindi/ English/Punjabi+19 channels
10	Jammu and Kashmir	424	Hindi/ English/Urdu+19 channels
11	Jharkhand	428	Hindi/ English/8hojpuri+19 channels
12	Karnataka	437	Hindi/ English/Kannada+19 channels
13	Kerala	451	Hindi/ English/Malyalam+19 channels
14	Madhya Pradesh	420	Hindi/ English/+19 channels
15	Maharashtra	438	Hindi/ English/Marathi+19 channels
16	Manipur	425	Hindi/ English/NE and Assamese+19 channels
17	Meghalaya	425	Hindi/ English/NE and Assamese+19 channels
18	Mizoram	425	Hindi/ English/NE and Assamese+19 channels
19	Nagaland	425	Hindi/ English/NE and Assamese+19 channels
20	Orissa	434	Hindi/ English/Oriya+19 channels
21	Punjab	441	Hindi/ English/Punjabi+19 channels
22	Rajasthan	420	Hindi/ English+19 channels
23	Sikkim	446	Hindi/ English/Bengali+19 channels
24	Tamil Nadu	462	Hindi/ English/Tamil+19 channels
25	Tripura	425	Hindi/ English/NE and Assamese + 19 channels
26	Uttaranchal	424	Hindi/ English/Urdu+19 channels
27	Uttar Pradesh	424	Hindi/ English/Urdu+19 channels
28	West Bengal	446	Hindi/ English/Bengali+19 channels
29	Andaman and Nicobar Islands	420	Hindi/ English+19 channels
30	Dadar and Nagar Haveli	420	Hindi/ English+19 channels
31	Daman and Diu	420	Hindi/ English+19 channels